

Yesterday, Dr. Pilaniaji had mentioned about the deaf and dumb problem. Ahluwaliaji has raised it again. Sir, this issue had come to the Ministry earlier. We had taken it up with the Finance Ministry which did not accept the suggestion as was made. But we will definitely take it up again because the manner in which and the sentiment in which it has been expressed, we agree with that sentiment. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, what about the creamy layer?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Wait, wait.

SHRI MUKUL WASNIK: About the creamy layer, the hon. Member is aware that it was right from the initial days in 1993 when the Supreme Court had decided on the issue. The creamy layer had come into effect since that time. Subsequently, in a different matter, in the year 2008 also, this issue had come up. What is with me at the moment is that, from time to time, whenever there is a need to revise the scales, the National Commission for Backward Classes goes into the issue. Recently, there was an enhancement of income criteria for the creamy layer.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch for one hour.

-----

The House then adjourned for lunch at thirty-four minutes past one of the clock

The House re-assembled after lunch at thirty-six minutes past two of the clock

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Prabhat Jha to start the discussion on the working of the Ministry of Communications and Information Technology.

#### **DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY**

**श्री प्रभात झा** (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यकरण के संबंध में अपनी चर्चा को आरम्भ कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर मनुष्य का स्वभाव जिज्ञासु होता है। वह जानना चाहता है, वह सुनता है, देखता है और महसूस करता है और उसके बारे में जानने की कोशिश भी करता है। जाने-पहचाने दो दिल, चाहे पास रहें या दूर, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वे एक-दूसरे के बारे में न जानना चाहते हों। यही कारण है जिसकी वजह से आदिकाल से संचार व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। विभिन्न युगों में इसकी व्यवस्थाएं अलग-अलग रही होंगी, लेकिन संचार कभी रुका नहीं है। जब मानव पढ़ा-लिखा नहीं था, तब वह मोम से, लकड़ी से, नुकीले लोहे से, पत्थर की नोंक से अपनी बातें लिखता था और संवाद करता था। पेरु में जो स्पैनिश लोग होते हैं, वे गांठदार रस्सी से कितनी गांठें बंधी हैं, उसके द्वारा संदेश भेजते थे और जिसको संदेश मिलता था, वह समझता था कि इन गांठों का क्या अर्थ होता है। इसी प्रकार प्राचीन काल में जब युद्ध होता था तो युद्ध के समय हरकारा राज्यों में दौड़ा दिए जाते थे। उसके साथ वह घोड़े पर चढ़कर जाता था और साथ में नुकीला भाला होता था। उस भाले पर मशाल जलती थी और रस्सी लटकती रहती थी। इसका मतलब यह होता था कि जो लोग युद्ध में भाग नहीं लेंगे, उनका घर जला दिया जाएगा, जो लोग लड़ाई में भाग नहीं लेंगे, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा।

महोदय, अब मैं डाक विभाग पर आता हूँ। 1836 में पहली बार रोलैंड हिल ने डाक व्यवस्था का सर्वेक्षण किया। आखिर डाक भारत की जिंदगी क्यों है, यह विभाग जिंदगी क्यों है, उसका एक उदाहरण है। 1836 में

रोलैंड हिल ने जब सर्वेक्षण किया तो उसने कहा कि जितनी दूरी पर डाक जाती है, उस दूरी के हिसाब से पैसा नहीं लेना चाहिए। उसने सर्वेक्षण पर रिपोर्ट दी कि पैसा पत्र के वजन के आधार पर लेना चाहिए। उसी समय से जितना पत्र का वजन होता है, उतना पैसा लगने लगा। इससे जाहिर होता है कि संचार जो है, जो डाकतार है, यह सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भारत का एक समर्थ साधन है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस विभाग की महत्ता सिर्फ मंत्रालय के नाते नहीं है, विभाग के नाते नहीं है। डाक गांव में एक परिवार के रूप में काम करता है। मुझे याद है, आप सबको भी याद होगा — पांच मिनट के लिए आप अपने गांव की तरफ चले जाएं या शहर के किसी इलाके में चले जाएं — वह डाकघर, वह डाक बाबू, वह डाकिया, उसकी साइकिल, उसकी खाकी पैंट, खाकी कुरता, खाकी शर्ट, लाल धारी वाली टोपी, उसकी घंटी की आवाज सुनते ही आंगन से दौड़ता हुआ बच्चा बाहर आता है और कहता है, डाकिया काका, क्या लाए हो? वह कहता है कि यह चिट्ठी लाया हूं। उस गांव का डाकिया कोई नौकर नहीं हुआ करता था, डाकिया वहां पर कोई employee नहीं था, वह उस पंचायत का, उस गांव का, अपने इलाके का एक संदेशवाहक होता था, परिवार का सदस्य होता था। कोई उसे काका कहता था, कोई उसे मामा कहता था और कोई उसे चाचा कहता था। इतने बड़े परिवार में, आपको आश्चर्य होगा कि अगर कोई निरक्षर होता था तो डाकिया उसकी चिट्ठी स्वयं पढ़ता था। अगर तार पर कोई दुखद समाचार होता था तो उसके हाथ कांपते थे कि मैं कैसे चाची को बताऊं कि परदेस में उसका जो रिश्तेदार रहता है, वह expire हो गया है। वह बताने में समर्थ नहीं होता था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े डाक विभाग में 6 लाख लोग काम करते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि डाक विभाग संस्कृति और परम्परा का हिस्सा हुआ करता था। आप सब कल्पना कर रहे होंगे तो आपको भी ऐसा ही लगा होगा। आज किसी बच्चे से पूछिए कि डाकिया क्या होता है, कौन है? वह कहेगा कालिया का भाई है। उसको पता ही नहीं है कि डाकिया क्या होता है। हमने एक संस्कृति को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। इस विभाग में लगभग 6 लाख लोग काम करते हैं और इसमें नियमित कर्मचारियों के अलावा ग्रामीण डाक सेवकों की लाखों में संख्या है। उपसभापति महोदय, इस ओर जब देखते हैं तो भारत में एक लाख पचपन हजार पैंतिस डाकघर हैं। यह 2008 की रिपोर्ट में है। इसमें एक लाख उन्तालिस हजार एक सौ तिहत्तर ग्रामीण डाकघर हैं 15,862 शहरी डाकघर हैं। जरा इन डाकघरों की स्थिति तो जाकर देखिए। अभी जैसे बरसात हुई तो वहां पानी टपकेगा। तो डाकघर की स्थिति क्या है? यह लाखों-करोड़ों रुपया आपको देता है, लेकिन उन डाकघरों की स्थिति देखकर आपको अजीब लगेगा। मैंने एक डाकघर में जाकर पूछा कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आपके यहां क्या-क्या हुआ है? उसने बताया कि कभीकभी भी पुताई हो जाती है, कभी-कभी रंगाई हो जाती है, यही हमारा मॉडर्नाइजेशन है। हम भारत को किस युग में ले जाना चाहते हैं? मैंने वहां एक और चीज देखी। हमने जो आधुनिकतम संचार व्यवस्था में मोबाइल वगैरह शुरू की है, तो इस संदर्भ में हमने सोचा कि चिट्ठियां बहुत कम जाती होंगी। मैंने इसकी भी जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि वोल्यूम और क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आई है, चिट्ठियां उतनी ही आ रही हैं, अन्तर इतना हुआ है कि पर्सनल चिट्ठियां बंद हो गई हैं, बिजनेस की चिट्ठियां ज्यादा आने लगी हैं, लेकिन चिट्ठियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। चिट्ठियां निरन्तर जा रही हैं, उसका स्वरूप बदल गया होगा, स्पीड पोस्ट से जाने लगा होगा, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आई है। आप लोगों को लगता है कि डाक का काम बंद हो गया है। सरकार का जो मंत्रालय है, वह भी लगभग उसी दिशा में चल रहा है, वह अन्य चीजों में जाने लगा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सन् 1984 से इस डाक तार विभाग में एक भी नियुक्ति नहीं है, इक्का-दुक्का हुई हो, तो हो सकती है, लेकिन 1984 के बाद कोई परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई है। अब देश की जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है? लेकिन आप देखेंगे कि डाकघर में नियुक्ति नहीं हुई है, डाकियों की संख्या नहीं बढ़ी है, डाक बाबू की संख्या नहीं बढ़ी है, जनसंख्या भले ही बढ़ गई हो, काम उतना ही है, इससे सारे लोग परेशान हैं। अब यहां पर एक और विडम्बना देखिए। इस विभाग में अगर कोई अनुकम्पा नियुक्ति होती है — मरसी अपोइंटमेंट, तो यह सदन सुनकर

आश्चर्य करेगा कि सौ डाक परिवारों में अगर कोई मृत्यु होती है, तो यह सरकार, यह मंत्रालय पांच लोगों को ही नौकरी देता है। यहां पर पांच परसेंट मरसी अपोइंटमेंट है। तो उन 95 परसेंट लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या अन्याय किया है उन्होंने? फिर यह पांच परसेंट अपोइंटमेंट किसकी मरसी पर होगा? कौन देगा इनको नौकरी, इसका क्या क्राइटेरिया है? मुझे लगता है कि इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अगर ग्रामीण डाक सेवकों की मृत्यु हो जाए, तो अनुकम्पा की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो ये मानकर ही नहीं चलते कि वे कोई हमारे कर्मचारी हैं। महोदय, आपने देखा होगा कि पहले रेलगाड़ी में एक लाल डिब्बा हुआ करता था। उस पर लिखा होता था - छडाक तार विभागाछ उस डिब्बे में चिट्ठियां बोरी की बोरी रहती थीं तथा पूरी बोरी में लोग छंटाई करते थे। डाकिये उसमें जाते थे, छंटाई कर चिट्ठियां अलग कर देते थे। लेकिन अब यह देखिए कि रेलगाड़ी में वह डिब्बा बन्द हो गया है तथा कुछ बोरी चिट्ठियां रखने के लिए छोटा सा स्पेस दे दिया गया है और उस स्पेस में चिट्ठियां रहती हैं, परन्तु उनकी छंटाई नहीं होती है। इसीलिए आज आपकी चिट्ठी दो दिन में नहीं पहुंचती है वह चार दिन में, पांच दिन में, दस दिन में पहुंच रही है। उसका बहुत बड़ा कारण है छंटाई न होना। 1986 से छंटाई होना ही बंद हो गया और जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं उनके बदले में किसी को नहीं रखा जा रहा है। डाक विभाग में एक आर.एम.एस. यानी शौर्टिंग ऑफिस छंटाई यह सब-विभाग हुआ करता था। वह पूरी तरह से बंद है।

एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक विभाग का काम आज भी मैनुअल हो रहा है। स्पीड पोस्ट के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन इसकी भी हालत खराब है। मुझे यह सुनकर आश्चर्य लगा, और यह मुझे डाकतार विभाग के लोगों ने ही बताया, कि भारत में जो प्राइवेट कूरियर सेवा है, यह डाकतार विभाग के अधिकारियों द्वारा बेनामी रूप से उनके द्वारा चलाई जाती है। 27 परसेंट डाक कूरियर से प्रभावित है। अब एक ताजा उदाहरण देख लीजिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर डाक विभाग का TMS office है। वहां कर्मचारियों की बहुत कमी होने के कारण ओवर टाइम करना पड़ता है। वहां के एक कर्मचारी ने मुझे बताया कि साहब, अगर हम काम से एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं, तो डायजनाल पनिशमेंट मिलती है। जब मैंने डायजनाल नाम सुना, तो मुझे लगा कि वह किसी दवाई का नाम बता रहा है। यहां डायजनाल का मतलब दवाई से नहीं है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अगर वह कर्मचारी एक दिन की छुट्टी लेता है, तो उसको ओवर टाइम भी नहीं मिलता है और जो उसने एक दिन पहले काम किया था, उसका भी पैसा काट लिया जाता है। यह इस डाकतार विभाग की कहानी है।

सर, मैं यहां संचार मंत्रालय के डाक विभाग में कार्यरत ग्रामीण सेवकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वे तीन से पांच घंटे तक काम करते हैं। पहले इन्हें ई.डी.पी. कहा जाता था, इन्हें काम नियमित कर्मचारियों की तरह से करना पड़ता है, लेकिन इनकी तरफ कोई नहीं देखता है, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इनकी पेंशन नहीं है, ग्रेजुविटी नहीं है, कोई चीज इनके लिए नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा गया और EDA को उन्होंने सिविल पोस्ट माना। उन्होंने कहा — They are the civil servant. लेकिन उसके बाद भी डाकतार विभाग कहता है कि हम ग्लोबल सर्विस सेंटर्स खोलने वाले हैं। आप इनको खोलिए, लेकिन आपके जो भारत में सेंटर्स हैं, पहले उनकी हालत सुधारिए। मेरा इतना ही निवेदन है। डाकतार विभाग के लिए वर्ष 2009-10 में 6021.26 करोड़ रुपये की मांग रखी गई थी। इस विभाग में 2008-09 के लिए संशोधित बजट 4228.78 करोड़ का था। आपने बजट को कुछ बढ़ाया है, लेकिन आपने परिवहन में क्या किया है? आपने परिवहन का बजट कम कर दिया है। गांव में जो गाड़ियां चिट्ठी लेकर जाती थीं, उनके लिए आपने बजट कम कर दिया है। आप किसी भी मुख्य पोस्ट ऑफिस में जाएं, आपने सेविंग वाले मामले में क्या किया है? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि चिट्ठी बांटने वाले से कहा जा रहा है कि सिनेमा के टिकट बेचो, रेल के टिकट बेचो, नरेगा में लगे। नरेगा में पूरे पोस्ट ऑफिस के लोग काम करते हैं। आपने क्या कर दिया है? आप एक संस्कृति को पूरी तरह से बदलने में लगे हुए हैं। केश सर्टिफिकेट के काम में काफी लापरवाही बरती जा रही है, यहां करोड़ों का घपला और भ्रष्टाचार जारी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह 2006-07 की सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है। उन्होंने कहा है कि आप यहां ध्यान दीजिए। यहां करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इस

तरफ आगाह करने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। आज़ादी के 62 वर्ष बाद भी एक संस्कृति और परम्परा से जुड़े इस विभाग की बहुत ही दयनीय हालत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह विभाग कितना मजबूत विभाग है। वर्ष 2003-04 में प्रीमियम सेवाओं की अतिरिक्त अधिकृत आय 425.74 करोड़ रुपये थे, आज 2008-09 में यह बढ़कर 2141 करोड़ रुपये हो गयी है। आपकी स्पीड पोस्ट की कमाई बढ़ गई है। नरेगा के दो करोड़ खाते आपके पास हैं, लेकिन न आपका डाकघर ठीक है, न आपके डाकिए की हालत ठीक है, न आपके डाकबाबू की हालत ठीक है, न डाक विभाग के ग्राम सेवकों की हालत ठीक है। आप इसके लिए क्या करेंगे? इतना ही नहीं है, कुछ यूनियन्स हैं, उन सभी यूनियनों को एक समान दर्जा दिया जाना चाहिए, आपके द्वारा वह भी नहीं दिया जा रहा है। डाककर्मियों के सभी वर्गों के लिए ए.सी.पी. योजना लागू होनी चाहिए, वह भी लागू नहीं हो रही है। आउटसोर्सिंग समाप्त होना चाहिए, वह भी नहीं हो रही है। भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन लिखित शिकायतों के बावजूद पता नहीं आपका मंत्रालय क्या कर रहा है? महोदय, यह तो थी डाकतार विभाग की कहानी। अब आ जाइए सूचना प्रौद्योगिकी पर। मैं आपको सुना रहा हूँ जुलाई, 2009 में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 2008 तक आईटी सुपर पावर बनाने का दावा हो रहा है। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यह अद्भुत लाइन है। यह मेरा कहा हुआ नहीं है। यह वेब साइट पर है। जुलाई 2009 में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत को 2008 तक आईटी सुपर पावर बनाने का दावा कर रही है। Department of Information Technology की वेब साइट पर मंत्रालय का विज़न लिखा है। “to make India an IT super-power by the year 2008.” इसका रेफ़रेंस भी है, जब स्वयं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट अपडेटेड न हो, तो यह मंत्रालय किस प्रकार की सूचना क्रांति इस देश में लाएगा, आप इसका अंदाज़ा स्वयं लगा सकते हैं। भारत को सन् 2008 तक IT Super Power बनाने की बात कही जा रही है। यह 2009 का जुलाई का महीना चल रहा है और सन् 2008 को बीते सात महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपका वही विज़न है और वही बात इस पर चल रही है। महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बारे में बता रहा हूँ। इस UPA की सरकार के सत्ता में आने के बाद इस सदन में तीन डाक्युमेंट्स आए हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है कि अगले तीन वर्षों में अपनी पंचायतों में भारत निर्माण सेवा केन्द्रों के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक शासन व्यवस्था होगी। मैंने आज तक यह नहीं सुना है कि कौन सी इलैक्ट्रॉनिक शासन व्यवस्था है। मैंने ई-गवर्नेंस तो सुना था, लेकिन इलैक्ट्रॉनिक शासन व्यवस्था, आदमी नहीं होगी, इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं काम करेंगी। इसके सिवाय अभिभाषण में एक भी बात Information Technology के बारे में नहीं कही गई है। जब कि आप इसको इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरा इकोनोमिक सर्वे है। आपने इकोनोमिक सर्वे में भी इन्टरनेट की बात की है, ब्रॉडबैंड की बात की, बाकी किसी चीज़ की बात नहीं है। और छोड़िए, जो आपका बजट पत्र है, उसमें भी आपने क्या किया है, इसमें Information Technology, सूचना प्रौद्योगिकी कोई शब्द नहीं है। आप कैसे 21वीं सदी लें जाएंगे और कैसे सुपर पावर बनाएंगे? यह आपका डाक्युमेंट है, मेरा नहीं है। महोदय, अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 5666 टावर लगाए गए हैं। मैं आपको 21वीं सदी के भारत की ओर ले जा रहा हूँ। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में इन टावरों की संख्या 4 लाख से ऊपर है। हर महीने शहर में 10 हजार से अधिक टावर लगाए जाते हैं, लेकिन एक-दो साल बीतने के बाद गांवों में 10 से 15 हजार टावर लगाए जाते हैं। आप देखिए कि गांवों में कम टावर लग रहे हैं, लेकिन आप पैसा किससे ले रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार विकास हेतु 5 परसेंट लेवी जो USO universal service obligation के अंतर्गत संग्रहित की जाती है, उसका 30 परसेंट भी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च नहीं कर पाई है। महोदय, इससे भारत के अंदर एक digital divide पैदा हो रहा है। ग्रामीण और शहरी भारत के बीच एक गहरी खाई बैठती जा रही है। इसका यह परिणाम हो रहा है कि आज हम कितनी बातें करते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम पाकिस्तान से भी इन्टरनेट यूज़ में बहुत पीछे हैं। इन्टरनेशनल टेलीकॉम्युनिकेशन यूनियन के अंतर्गत Nilson online अध्ययन के अनुसार कहता है कि जहां भारत में जनसंख्या का 7.14 प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करता है, वहीं पाकिस्तान में 10.01 प्रतिशत है और चीन में 22.4 फीसदी इंटरनेट का प्रयोग होता है।

आखिर ग्रामीण लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? भारत के गांवों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप इस तरह का क्यों भेदभाव करते हैं? आपको इसके लिए प्रयास करना होगा कि गांवों का भेद मिटे और आपका मंत्रालय गांवों के साथ भेदभाव न करे। आप इन बेसिक चीजों पर नहीं जाते हैं।

उपसभापति महोदय, मैं आप से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो कुछ भी होता है, सब जोश खरोश में हो जाता है। पहले निर्णय फिर घोषणा होती है और इम्प्लीमेंट के जितने तरीके हैं, उनमें यह नहीं देखा जाता है कि यह होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं मुम्बई में पढ़ता था और यह सन् 1964 की बात है। मैं 1964 में अपनी बहन की शादी में बिहार गया था। मैं मुम्बई जैसे शहर से गांव में गया था और मैंने वहां देखा कि सब जगह अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने अपने बाबा से पूछा कि बाबा आपके गांव में बिजली क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि देखो यह बिजली का पोल आ गया है और उन्होंने मेरे मुंह में गुड़ का ढेला डाल दिया तथा कहा कि चुप रहो। उन बातों को दो साल बीत गए और सन् 1966 का वर्ष आया तथा मेरे बाबा नहीं रहे। मेरे पिता जी उस उम्र में पहुंचे और मैं भी थोड़ा बड़ा हुआ। मैंने पिता जी से कहा कि अभी तक वह बिजली नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है तो तालाब में, पोखर में जाकर नहा आओ, लेकिन ज्यादा बोलो मत और मैं चुप हो गया। महोदय, इसके बाद थोड़ा और आगे चलें, सन् 1993 में मेरे पिता जी की भी मृत्यु हो जाती है तो मेरा पांच साल का बेटा मराठी संस्कृति से है, वह मुझसे पूछता है कि बाबा तुम्हारे गांव में लाइट नहीं है? मैंने कहा कि फिर बेटा हम क्या करें? हमने कहा कि हमारे पिता जी के पिता जी ने बिजली नहीं देखी। मेरे पिता जी के पिता जी ने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी....। मेरे पिताजी ने नहीं देखी, मैं तेरा पिता हूँ, मैंने नहीं देखी, पता नहीं तेरी शादी के बाद जब तू पिता बनेगा तो बिजली देखेगा कि नहीं देखेगा। हम इस युग में कम्प्यूटर की बात कर रहे हैं। साठ हजार गांवों में बिजली नहीं है, आप कम्प्यूटर कहाँ लगाओगे? मैं आधुनिकतम चीजों का, मॉडर्नाइजेशन का विरोधी नहीं हूँ, खूब संचार कीजिए, लेकिन आप पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर तो तय कर लीजिए। आप यह सब नहीं कर रहे हैं। इसका बेसिक कारण क्या है, हमारे देश में कम्प्यूटर का उपयोग क्यों नहीं बढ़ रहा है, कम्प्यूटर के प्रति लगाव क्यों नहीं बढ़ रहा है? कारण यह है कि भाषाओं के ऊपर हमने कोई प्रयत्न ही नहीं किया है। हमारी भाषा हिंदी है, अंग्रेजी के माध्यम से चलना चाहिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की प्रभावी उपस्थिति दिखा सकें। चीन में भारत से अधिक लोग अंग्रेजी समझते और बोलते नहीं हैं, उनकी अपनी भाषा है। वे अपनी भाषा के आधार पर देखते हैं और आज भी वहां हम से तीन गुणा लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। भारत में हम इंटरनेट और दूर संचार के साधनों के माध्यम से अगर अंग्रेजी को बाहर करने का सोचें तो सब डंप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम इस तरफ प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? हमारा मंत्रालय इस तरफ क्यों नहीं देखना चाहता है? हम छोटे-छोटे गांवों में पहुंचना चाहते हैं, तो हमें भाषा का सहारा लेना होगा। भाषा तकनीक के विकास के लिए आप इस विभाग की मज्जेदार कहानी देखिए कि भाषा के विकास के लिए या तकनीकी डेवलपमेंट के लिए जितना पैसा पिछले वर्ष रखा गया था, उतना ही पैसा इस बार रखा गया है। आपकी किसमें रुचि है? आप विकास करना नहीं चाहते हैं। आपने अपना 2600 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। आपने कहा सूचना प्रौद्योगिकी बजट में पिछले वर्ष 7.89 करोड़ की राशि थी, उतनी ही राशि आपने इस वर्ष भी तकनीकी विस्तार के लिए रख दी है। आगे आइए — जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 6 करोड़ रुपए थे, इस बार भी 6 करोड़ रुपए हैं। यह आखिर है क्या? आप क्यों महिला अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति पर अन्याय करना चाहते हैं? क्या आप वहां तक आई.टी. को पहुंचाना नहीं चाहते हैं? क्या इन चीजों को गांव से महरूम रखना चाहते हैं? यह आपको देखना पड़ेगा। मैं आपके अच्छे निर्णयों का स्वागत भी करना चाहता हूँ। आपने कहा है, बिहार में घोषणा भी की है, दस पैसे प्रति मिनट पर टेलीफोन कॉल्स की बात कही थी, लेकिन देखकर आश्चर्य होगा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आपने घोषणा की है, यह अच्छी बात है, लेकिन आप इसको पूरा कीजिए। मैं आपसे इसके आगे कहूंगा कि अगर दस पैसे प्रति कॉल

3.00 P.M.

के हिसाब से आप लेते हैं तो उसी रेट से, काफी कम रेट पर गांव के लोगों को इंटरनेट भी उपलब्ध हो सकता है। मोबाइल नम्बर प्रोटेबिलिटी (एम.एन.पी.) की घोषणा तो आपने कर दी, लेकिन यह कहाँ है? आपका यह एम.एन.पी. कहाँ चला गया? वाइस ओवर इंटरनल प्रोटोकॉल पर आज तक आपने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है, जबकि इसे उठाए बिना आप गांव में जा नहीं सकते हैं। आज विदेशी कंपनियां भारत में वी.ओ.आई.पी. धड़ल्ले से बेच रही हैं, परंतु भारत में कुछ निहित स्वार्थों को संरक्षित करने के लिए इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। जहां आपकी अनेक योजनाओं की बात है, आप घोषणा करते रहिए, सब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। दूसरी ओर आप देखिए, ध्यान से सुनिए कि एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल., जो नवरत्न कंपनियों में गिनी जाती हैं, आज अपना बाजार प्राइवेट ऑपरेटर्स के हाथों में खोती जा रही हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्स को मंत्रालय ने अनावश्यक और अनैतिक छूट दे रखी है, जबकि एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. को इनके साथ नियमों के अधीन प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है। अब आप देखिए कि प्राइवेट ऑपरेटर्स 128 केबीपीएस स्पीड को ब्रॉड बैंड कहकर खुले आम बेच रहे हैं, जबकि 256 केबीपीएस से कम स्पीड को ब्रॉड बैंड कहा ही नहीं जा सकता। इस तरह आम जनता के साथ कौन फ्राँड कर रहा है? आपका मंत्रालय, आपका विभाग। यूरोपियन देशों में जहां आज भी 64, 128 एमबीपीएस इंटरनेट की बात कही जा रही है, भारत में अभी भी 16 एमबीपीएस तक ही सोचा जा सकता है। मैं आपको एक मिनट के लिए एनडीए शासन में ले जाना चाहता हूँ। आप देखिए, उस समय कितना काम हुआ था और आज आपके कंप्यूटर के युग में, इन्फोर्मेशन टेक्नॉलॉजी के युग में कितना काम हो रहा है। होस्टिंग कंपनियों का मामला आपके सामने आया होगा। यू.एस. में पच्चीस हजार से अधिक होस्टिंग कंपनीज हैं और भारत में बमुश्किल बारह सौ कंपनियां होंगी। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो जो बारह सौ कंपनियां हैं, उनका सर्वर यू.एस. में है, भारत में नहीं है, यानी यह सुरक्षा के लिए कितना घातक है। यदि हमारे सभी तरह के डाटा, सरकारी, गैर सरकारी, व्यापारिक से लेकर सुरक्षा तक की संवेदी सूचनाएं यू.एस. के सर्वर पर उपलब्ध हैं, तब यह हमारी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत घातक है।

यह आपको सोचना होगा। Hosting का काम भारत में हो सकता है, परन्तु आपका मंत्रालय इसे करना नहीं चाहता है और करने नहीं देना चाहता है।

अब देखिए, सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर की बहुत बातें होती हैं। मैं आपको उसकी कहानी सुना देता हूँ। **(समय की घंटी)** जहाँ तक सॉफ्टवेयर का प्रश्न है, देश ने निजी कंपनियों के माध्यम से प्रगति की है। हम इसकी सराहना करते हैं। यह सराहनीय है, परन्तु यह प्रगति मूल सॉफ्टवेयर के आधार पर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में है। आज तक सरकारी क्षेत्र में सरकार द्वारा कोई भी ऐसी संस्था नहीं खोली गई है, जो मूल सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए विश्व में विशिष्ट तौर पर कार्य कर रही हो। दुर्भाग्य की बात है कि मूल सॉफ्टवेयर अर्थात् सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें आपरेटिंग सिस्टम हो, डाटा बेस मैनेजमेंट हो, सिस्टम नेटवर्क हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो, यूआरबी हो, इन क्षेत्रों में भारत देश के रूप में हम कहीं भी ऐसा नहीं कहते। उपरोक्त सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक भी सॉफ्टवेयर में भारत का अपने नाम का ब्रांड है ही नहीं।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले दो मोटी-मोटी बातें कहना चाहता हूँ। आप बीएसएनएल की स्थिति देखिए। इसमें 97% की भारी गिरावट आई है। 20 जुलाई 2009 को टाइम्स ऑफ इंडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे पास है, बीएसएनएल के निष्पादन पर एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मात्र 2 सालों के भीतर बीएसएनएल के लाभांश में 97 फीसदी की भारी गिरावट आई है। गौरतलब है कि सेना और रेलवे के बाद बीएसएनएल में सर्वाधिक सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। बीएसएनएल का देश के आर्थिक विकास में काफी अहम रोल है, क्योंकि सरकार को हर वर्ष कर व लेवी के रूप में 24 हजार करोड़ से 30 हजार करोड़ रुपए तक इसका योगदान होता है। उपसभापति महोदय, 2008-09 में बीएसएनएल का शुद्ध लाभ मात्र 104 करोड़ रुपए था, जबकि 2007-08 में इसका शुद्ध लाभ 3,009 करोड़ रुपए था, जबकि 2006-07 में बीएसएनएल का शुद्ध लाभ 11,806 करोड़ रुपए था।

अब एमटीएनएल पर आ जाइए। (समय की घंटी) मैं समाप्त कर रहा हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुम्बई और दिल्ली में टेलीफोन सेवाएँ मुहैया कराने वाली सार्वजनिक उपक्रम एमटीएनएल का एक तिमाही के दौरान घाटा 83 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। एमटीएनएल के खस्ताहाल की असली वजह सरकार की बदइंतजामी है, न कि वैश्विक मंदी। हम कह देते हैं कि वैश्विक मंदी के कारण यह सब हो रहा है। ऐसा नहीं है। एमटीएनएल के पूर्व सीएमडी एस. राजगोपालन का मानना है कि आने वाले वर्षों में एमटीएनएल की तरह बीएसएनएल की स्थिति भी खराब हो जाएगी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है, “If we do not free MTNL from the control of the Government, it is going to be doomed soon. BSNL will also follow the same path and will become ran player in few years.” It is given on page 27 of Telecom LIVE June, 2009. यह हालात है आपकी दुनिया की और आप कह रहे हैं कि हम भारत को 21वीं सदी में ले जाएंगे। यह धोखा आप न भाजपा को दे रहे हैं, न सांसदों को दे रहे हैं, यह धोखा भारत को है और भारत को धोखा देना बहुत बड़ा पाप है। आप इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर की दुनिया में गुलामी से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको अपनी चीजें खड़ी करनी होंगी। मुझे लगता है कि यह विभाग निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देगा। धन्यवाद।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Mr. Deputy Chairman, Sir, we are here discussing the working of the Ministry of Communications and Information Technology.

Sir, at the outset, I would like to salute our great leader Shri Rajivji who brought in this concept of modern India through the medium of electronics. He started with television, mobile, etc. When Rajivji was picking up internet, a great leader of a political party remarked that Rajivji is moving with a *dabba*. राजीव जी, इस डिब्बे से क्या कर लेंगे। He was humiliated at that stage and today, that *dabba* or that internet system has created wonders in every field of life, not only for the elite class, but also for farmers, labourers and everyone in every nook and corner of the country. ...*(Interruptions)*...

**श्री राजीव शुक्ल: \***

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... That will not go on record. जो अपनी सीट से नहीं बोलेंगे, वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: They know it and everybody understands it. Sir, I need not name who said that. Sir, in spite of the world recession, it is a good sign that our information technology industry has not suffered to that extent. Indian information technology business shows a substantial growth in 2008-09; revenue aggregate of ITDPO industry is expected to grow at 12 per cent in 2008-09; Indian IT software and service export is estimated, in 2008-09, to grow at 16.3 per cent, and service export, by 16.5 per cent. This is a brief scenario of information technology.

Now, Sir, there are three or four concepts which come for our help. These are National e-Governance Plans, State Wide Area Networks (SWAN), State Data Centres and Common Service Centres. It is with these instruments and with these programmes that the country is marching ahead. But I would like to tell the hon. Minister that these programmes are overlapping and, sometimes, it becomes difficult for us to understand which is the area of each of these

---

\*Not recorded.

programmes. Ultimately, it means, we would like to have e-governance in the entire country, whereby information concerning any activity of the Government is available. Suppose the Government or the Parliament enacts rules and regulations. They will be immediately available on the network, whoever wants to use them. Details about schemes of the Government, specially schemes with prescribed forms, are, partly, made available by some Departments. But all that can be made available through this system because there will be Common Service Centres throughout the country, and these Common Service Centres are going to help the common men in every village of the country. If a person desires to take a loan for some purpose, he will have to fill up a prescribed form under the scheme; he need not have to go to the *taluka* office. He will have to only pay some minimum amount to these Service Centres for getting that form. He can fill it up then and there, and even submit it to the Service Centre. This is the system which is envisaged and which is going to come in the future. Therefore, it is going to create a revolution. I would like to suggest, although this does not, directly, come under this Ministry, that all those concerned should place the Government of India gadget on the website. I do not know whether it is available today. If a gadget is available, if all the issues of the gadget are available, then, by just one stroke, you can provide information concerning all the Government activities, throughout the country, in just one hour's or two hours' time. Therefore, the Departments concerned will have to use this technology for the purpose of providing information.

To start with, Sir,—it concerns the Chair also—we, in the Parliament, have also to use this technology to a greater extent. Sir, I have always been submitting that at 12 o'clock, we get Unstarred Questions' copies here. If the same questions, in electronic forms, are provided on the website, it will help us a lot. They are available on the website only after three days! When, through this technology, hard copies are available, I don't think it is difficult for them to supply, at the same time,...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is for the Ministries to send soft copies to the Parliament. Then, we will happily do that!

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: You will be surprised to know, Sir, that we have been searching for these Annual Reports and we have been pleading with the distributing centres for getting Annual Reports. Why is the Annual Report of our Ministry, which deals with information technology, not available on the website of the Ministry? This is very shocking, I would say.

I can excuse other Ministries. But if the Annual Report of the Information Technology Ministry is not available on the website, what can I say, Sir? Therefore, Sir, I would like to submit that Annual Reports of Ministries and Standing Committee Reports should be made available on the website immediately. Sir, the Chair should give a direction in this regard. I would like to point out that we get replies, from the Ministers, to letters we write, and other things, only after two months or three months. Now, they can start a system of e-mail by which they can reply to those who give the option so that the one or two lines, whatever the reply that they give — on



ninety per cent of the occasions they give negative reply — let that reply come through e-mail so that we can have it speedily.

Another issue is — I am referring to my State of Goa; I have mentioned it to the hon. Minister; I am confident that he will do it — that the Telecom Department and the Postal Department are treating the fullfledged State of Goa as a district. When we are constitutionally a State, we are entitled to have a circle. You can't reduce our status to a district. Therefore, I plead with the hon. Minister that Goa should be given an independent telecom and postal circle or whatever it is. Just because it is a small State, you can't merge it with Maharashtra. We fought against and opposed merger with Maharashtra politically also. Now, the Postal Department is treating us as a district which is not fair. I urge upon the Minister to create a separate circle for Goa.

Another important aspect of e-governance is computerisation of land records. Many States are doing it. Survey plans, land records and rights, etc., should be available on computers. Now, the survey plans are available on computers. They have to go ahead with computerisation of transfer deeds, sale deeds, gift deeds, etc. They should be made available on computers. In Goa there is a system called land registration which is not available anywhere in the country. The property is registered under land registration which is a title. This system should be computerised and made available on computers so that the information would be available by pressing a button.

Regarding the BSNL Mobile System, everyone is suffering from it. We have been given the Dolphin cards. If you dial for three minutes or if you get a call for three minutes, there will be interruptions, at least, twice or it will be disconnected twice. The GPRS system is not working at all. It works sometimes at a very few places and sometimes it does not work at all. There is no speed at all. The speed of broad band is also not satisfactory. If you want to download from a video clipping, the speed and the system is of no use. Now, 3G System is coming. I hope that the 3G System will be effective and, at the same time, the hon. Chair will grant us this facility and provide this facility to all the Members of Parliament. Shri Raja will ensure that the 3G System is a perfect system.

As far as translation of data from one language into other languages is concerned, it is very important. I think some programme or some software is being developed whereby you can have the translation. Suppose there is something in English language. I want a translation of it in my language Konkani, it should be available. It should be available in all the languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution. I understand that a software is being developed. I urge upon the hon. Minister that this technology should be made available at the earliest. It would be useful to all print media and electronic media, those who do research, etc. This is a very useful system. I don't know what the present status of this software or programme is. I would like to urge upon the Minister to refer to this aspect when he replies to the debate.

Similar is the case with Grandhalayas. E-Grandhalayas will be the future of libraries in the villages because purchasing books will be very costly. The village libraries can't afford to purchase books. If they have a computer and they have internet connection, it is so simple. With this electronic books will come in and this will go a long way in helping the people.

Cyber crimes are a matter of concern. The Information Technology Act has been amended recently and certain good provisions have been incorporated. Regarding cyber crimes, I think some knowledge should be imparted to the students in schools and colleges. The students who go to porn sites and other sites, they are not aware of the consequences. They are not aware of the law, that if you get access into somebody's system, with malicious intent, you can be arrested. So, there will be cases of young boys and girls being arrested and put in jail because the offence is of serious nature. Therefore, in every school and college, students must be imparted knowledge about these cyber crimes. Otherwise, police will bring to book hundreds of students every year, and that will also be a social problem. Now, as far as unsolicited calls and unsolicited SMSs are concerned, I made a submission last time that in case of companies, which send these unsolicited SMSs, their Directors should be arrested and put in jail. Also, they should be given a mobile phone with only the incoming facility, and for the whole month, such SMSs should be sent repeatedly to them. Only then will they understand the problem. This is a serious thing. It so happens that even at night time, we get such SMS; thinking that it could be an urgent message, we open it. Kindly take it seriously.

Then, there was one proposal for mobile number portability. It is that even if we change the service provider, the number would not be changed. I note that such a scheme is there in the pipeline. I would like to know from the hon. Minister as to what the position is about the mobile number portability. It will be very useful that even if we change the service provider, we will get a different card, but the number will not change.

As far as the Right to Information Act is concerned, — it is a connected issue — it is going on well in the country. Various countries are praising us for this. The NGOs are using it; the common citizens are using it. But, what happens is that officers get constantly engaged in this task of supplying the information. I would say that almost 80 per cent of the information can be put on the web site. If this is done, then, there will be no need for getting the information manually from various departments. I can understand that some notings, etc. have to be supplied. But if most of the statistics and data are made available on the web site, then, there will be no need for anybody to make a separate application for obtaining the information. Therefore, some initiatives have to be taken at the Centre to advise the State Governments also to see to it that important data, which the people would normally like to have, are made available on the internet.

Now, Sir, in the Information Technology, my learned colleague also referred to postmen. While speaking of the internet and other advancements that we have in this field, I would not like

to forget the poor postmen who have played an important role in our lives. I still consider that postmen are the lifelines of villages in this country. In this connection, I remember a song which glorifies a postal letter.

सर, आपने यह गाना सुना होगा,  
चिट्ठी आयी है, वतन से चिट्ठी आयी है  
बड़े दिनों के बाद, हम बेवतनों को याद,  
वतन की चिट्ठी आयी है, चिट्ठी आयी है।  
ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है,  
ओ परदेश को जाने वाले,

**श्री एस.एस. अहलुवालिया:** तरन्नुम में सुनाते तो ज्यादा अच्छा होता।

**श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक:** लौट के फिर न आने वाले

सात समुंदर पार गया तू,  
हम को जिंदा मार गया तू,  
खून के रिश्ते तोड़ गया तू,  
आंख में आंसू छोड़ गया तू,  
कम खाते हैं, कम सोते हैं,  
बहुत ज्यादा हम रोते हैं।  
चिट्ठी आयी है, वतन से चिट्ठी आयी है।

I honour the postmen of our country. With these words, I conclude. Thank you, Sir.

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Sir, at the beginning of my speech, I would like to mention, very quickly, an aspect relating to the Demands for Grants. Now, this is with respect to Demand No. 14. I see that there is a huge amount of financial relief for the ITIs, which is to the extent of Rs. 2,820 crores for 2009-10. But I have seen here that nothing was allotted for the year 2008. These ITIs have been working in our country since 1947. In the year 2007, there was an allotment of Rs. 729 crores. I do not know the planning of the Government. There are six of these ITIs. One is in Palakkad which is in profit. But the other five are in losses. There is the issue of revival or closure. Please come to the House with a clear concept so far as these ITIs are concerned.

Then, under Demand No. 15, Item No. 11 is regarding Manpower Development and there is no enhancement in the allocation meant for this. In Item No. 11, meant for Development Programmes, it is stated, "The objective of the programme is to create and strengthen the specialized manpower required to support the growing software export industry and to achieve the targeted export". But, there is no increase in the allocation this year. I do not know how it will be possible. Then, there is another item under Demand No. 15, namely, Item No. 20, 'IT for Masses' where you talk about women empowerment and reducing the gender bias as also manpower development of Weaker Sections (SC/ST). But, again, there is no enhancement in

allocations as compared to the last year. In that case, how will this Ministry perform so far as these objectives are concerned? Then, Item No. 24 is about the National Knowledge Network. The allocation last year was Rs. 91 crores. This year, the allocation is of Rs. 540 crores which means a 493 per cent increase as compared to the last year. It is a big jump. Then you talk of multiple gigabit bandwidth to connect knowledge institutions across the country. I do not now how it will be possible in one year. Then, for the entire North-East, there is a lump-sum allocation in this Budget. There is a big jump in comparison to the previous year. I would like to have the hon. Minister's reply as far as my observations pertaining to Demand No. 14 and 15 are concerned.

My next point is about the working of the BSNL. Already, many hon. Members have mentioned this. But I have a break-up of the data which I want to share with you. Eighty-five lakh wired lines have been surrendered. Seventy lakh mobile connections of BSNL have been surrendered. Sir, 12.7 lakh WLL connections have already been surrendered. Taking all these together, 1.68 crore subscribers have already surrendered BSNL connections of different types. There are two factors responsible for this. One is the inefficient customer care and the second one is the non-payment. Now, what is the planning of the Government? Sir, BSNL, is an important public sector unit. And, all this has happened in less than two years. What is the planning of the Government? There is one other thing that I would like to mention here, Sir. Sir, there is a noise in the market and the noise is that BSNL is in a poor financial situation. Just after it started in 2000, it had earned profits to the extent of Rs. 8000 crores, 10,000 crores, Rs. 11,000 crores. And suddenly, one fine morning, you find that the profit has gone down to just Rs. 104 crores. I must say that the Government has already started making efforts for listing BSNL in the Stock Market and it is before that that this noise about declining profits has come, maybe to depress the market sentiment and to sell the shares at cheap prices.

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair]

I am afraid; this is being done there. Sir, there is a funny thing, so far as the BSNL is concerned. Here, I would like to say that in the cash reserves section, the BSNL has Rs. 37,000 crores. It has deposited money in the bank at six per cent interest rate. But, it is also said in the Report that the BSNL borrowed money from the financial institutions at 14 per cent interest rate. Why is the Government doing this? It is a public sector unit; people's money is involved in it. Why are you not caring for people's money? I am saying here that many people are not using the BSNL. Why? It is because there is a phrase, so far as the BSNL name is concerned. 'भाई साहब, नहीं लगेगा — BSNL'. In the remote villages, there is no connectivity; in the entire North-East area, BSNL is not performing well; in the border area, BSNL is not performing properly. In this perspective, BSNL should strengthen itself. So, I hope that the hon. Minister would come up with a comprehensive reply. Sir, C-dot was started in 1984, as I remember. Then, what is the

performance of C-dot, which belongs to this Ministry? The CAG Report says 'that out of 23 projects, technology was developed only in 11 projects, partially in four projects'. I can give the para number also. It is said in para number 1.6.4. Two, internal revenue generation of C-dot has declined by 78.5 per cent from Rs. 33.11 crores in 2000-01 to Rs. 7.12 crores in 2005-06. There is a sharp decline in royalty, which is 96.1 per cent. The revenue from DOT declined by 95.73 per cent. It is stated in the CAG Report of 2007. 'Provide market orientation to research and development activities and sustain C-dot as a centre of excellence'. It was one of the objectives of C-dot when it was started, but the Ministry is declining to help C-dot to improve its performance.

Sir, now I would like to say something about the PSUs in the telecom sector. These PSUs are our national property. The role of telecom PSUs in regard to overall expansion of telecommunication is reducing. It is a very dangerous sign. A very dangerous situation is ahead of us. In 2007, December, Sir, it was 27.64 per cent, and in 2008, May, it is 25.25 per cent. Big giants are in the field; they are in the picture. Bharti, Reliance, Tata, Vodafone, etc., who have banned Indian presence, the Department itself gives them space. I would like to know about the plan of the Government to make the PSUs competitive. The Government should save our national property. You are talking of aam aadmi; everybody is talking about the common man. Everybody is talking about the aam aadmi, but, you cannot deny that aam aadmi's money, hard-earned money, is in the public sector units. Don't try to sell it; don't try to do anything, so far as the PSUs are concerned.

Sir, the Village Telephony, VTP is one of the important sections of this Department, but till date, as I remember, nearly 3000 villages are not yet connected by telephone. Many times, we have seen the reports in newspapers that they are trying their best to provide telephone in every village. I have seen in the Annual Report for the year 2008-09 also. But there are about 3000 villages, which do not have even a single connection. It is one thing. The other thing is that I have seen the Annual Report of this Department in which they are saying 56,000 or 57,000 villages are covered by telephony. I do not know whether there is any monitoring system or not. Villages covered under this scheme have been provided with one single telephone but these telephones are not working and the common people are not getting the facility of talking to their relatives like brothers and sisters who are living outside the village. Another point is about teledensity in the rural areas. Rural connectivity is the thrust area. Every time the Minister has told that it is planned that in the Eleventh Plan period up to 2011-12, there will be connectivity for 200 million people till 2012. But what is happening is that performance as on 31st January, 2008, is 8.68 persons for 100 people. So, target for teledensity is 25 per 100 hundred people. This shows that this Department has utterly failed. Teledensity is going up in the urban areas as has been told by the initiator of the debate but in the rural areas teledensity is not growing so fast. It is very much required in the rural areas. So far as the teledensity is concerned, what is the plan of the Government for the rural areas? ...*(Interruptions)*...*(Interruptions)*... *(Time-belling)* Sir, what is my time?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) You have only one minute. ...*(Interruptions)*... Out of 14 minutes, you have taken 13 minutes. Take two more minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI MOINUL HASSAN: I am your very obedient Member. ...*(Interruptions)*... Sir, another point is about sharing of infrastructure of mobile service scheme. What is happening? It was announced by the Government that 7871 towers were to be set up for mobile phones in 500 districts of 27 States. It is also for the mobile service in the remote areas and rural areas also. Everybody is waiting for that. But what is happening? It is reported in the Annual Report that up to March 2009 installation has taken place for 4755. It is only installation and not commissioning. I know they have been installed but not commissioned. There is a huge number of remaining towers. What is the opinion of the Department through their Annual Report? It says that remaining towers are now in different stages of installation. What is this 'different stages' about that no clear-cut indication has been given as to when these towers will be installed and commissioned. The Ministry must explain because there is already a considerable delay. There is no doubt about it. One thing that I submit is that I have a fear that delay is for nothing but in the meantime, the private provider will take over in these remaining areas. It is for this reason that this delay is taking place. Another point is when the initiator started very eloquently in Hindi, he told about what was the dak system in our country especially in the village areas. The system we had during our boyhood is no more there. It was very much assimilated in our culture. It is no more a Government system now. That culture has lost. It has lost its credibility. A parallel system is going on. **(Time-bellring)** Post offices are being used for other purposes. They are in a vulnerable situation. In the name of modernisation, nothing is happening. The village dak system should be revived. The ED, Extra-departmental personnel should be made permanent. Those ED personnel who are working in the rural areas should be made permanent. With these words, I conclude my speech. Thank you.

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन):** श्री कमाल अख्तर। कमाल अख्तर साहब, आपकी पार्टी का पूरा समय 13 मिनट है और आपकी पार्टी की तरफ से दो नाम दिए गए हैं।

**श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश):** सर, आधा-आधा बांट दीजिए।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन):** ठीक है। पहले स्पीकर को सात मिनट मिलेंगे और दूसरे स्पीकर को 6 मिनट मिलेंगे।

**श्री राम नारायण साहू:** हमने पहले नाम लिखवाया था।...*(व्यवधान)*...

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन):** ठीक है। आप बैठ जाइए।

**श्री कमाल अख्तर (उत्तर प्रदेश):** धन्यवाद महोदय, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि communication sector दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण और रूप रहा है। वास्तव में आईटी और टेलीफोन ने पूरी दुनिया के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किया है। मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि वर्ष 2009-10 में एमटीएनएल को 1725.02 करोड़ और बीएसएनएल को 14015

करोड़ रुपए का आबंटन हुआ था। मैं बताना चाहता हूँ कि भारत की 70 प्रतिशत आबादी गांवों के अंदर रहती है। एमटीएनएल शहरों के अंदर काम करता है जबकि बीएसएनएल ज्यादातर गांवों और देहातों के अंदर टेलीकॉम की सुविधा मुहैया कराता है। उसके बावजूद उसका बजट एमटीएनएल की तुलना में प्रति उपभोक्ता बहुत कम है। आंकड़ों के हिसाब से 41.5 करोड़ मिलियन मोबाइल कनेक्शन और करीब 30 मिलियन लैंडलाइन कनेक्शन हैं। हम 3जी की बात करते हैं। एक करोड़ मिलियन कनेक्शन हर महीने जनता अपने लिए लेती है। चाहे किसी भी कम्पनी के मोबाइल का कनेक्शन हो, आज लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि कोई भी जब कहीं मोबाइल मिलाता है, किसी से बात करना चाहता है तो मालूम होता है कि दूसरी जगह मोबाइल मिल गया। एक दिन मैंने कहीं फोन मिलाया और जब मैं उनसे बात करने लगा तो उधर से किसी महिला का फोन मिलता है और सुनाई देता है कि आज कौन सी सब्जी आपके यहां पकी है। इसमें सिग्नल्स की यह हालत है कि जैसे हम लोग मुम्बई या कोलकाता से कभी शाम के समय आते हैं और एयरपोर्ट पर जब जहाज लैंडिंग के लिए पहुंचता है तो एक घंटे का सफर होता है और एक घंटा कंजेशन की वजह से लैंडिंग नहीं हो पाती है। वही स्थिति मोबाइल की है। शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप कितना ही नम्बर मिलाते रहिए, कहीं आपको फोन नहीं मिलेगा। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि signal failure और network connection की समस्या से सभी रुबरू हैं। TRAI ने 2005 में service providers को इस संबंध में कुछ directions दी थीं। इस संबंध में 6 मोबाइल ऑपरेटर्स के खिलाफ show cause notice भी दिया गया। TRAI ने 1 जुलाई, 2009 से call drop rate तीन से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया पर इस दो प्रतिशत को 8 प्रतिशत पर क्यों नहीं लाया जा सकता? सरकारी और प्राइवेट कम्पनियां जानबूझ कर यह सब कर रही हैं। सर, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि आज बीएसएनएल की फुल फॉर्म हो गयी है “भाई साहब नहीं लगेगा”, क्योंकि फोन लगता ही नहीं है, चाहे कोई कितना ही फोन मिला ले। आज हम लोगों के पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा ढांचा पूरे देश के अंदर हम लोगों के पास है, लेकिन प्राइवेट कम्पनियां हम लोगों से connectivity और clarity दोनों चीजें अच्छी दे रही हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कहीं यह एक साजिश तो नहीं है? कहीं इस संस्था को, इतनी बड़ी कम्पनी को प्राइवेट सेक्टर के अंदर ले जाने की या उन लोगों को लाभ पहुंचाने की इन लोगों की साजिश तो नहीं है? कहीं जो सरकारी लोग हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, ये लोग मिल तो नहीं गए हैं? हमारे पास इतना बड़ा ढांचा है कि वे हमारे सामने हर मायने में, हर मुकाबले में कमजोर हैं। सर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर फोनों की सुविधा का बुरा हाल है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2009 को 16.54 प्रतिशत tele density है और भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा 66,822 गांवों में से 57,595 गांवों में विलेज पब्लिक टेलीफोन द्वारा टेलीफोन सुविधा मुहैया कराई गई है। बाकी गांवों में नवम्बर, 2009 तक वी.पी.टी. सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। वास्तविक स्थिति यह है कि अधिकांश फोन या तो काम नहीं करते या लाइन व्यस्त पड़ी रहती हैं या आउट ऑफ ऑर्डर हैं या डेड हैं। सर, स्थिति यह है कि जो टॉवर हैं उनको ऑपरेटर रात को बंद कर देते हैं। वे इसलिए बंद कर देते हैं कि उनको डिपार्टमेंट से जो तेल मिलता है उसको चोरी कर लेते हैं, क्योंकि उन ऑपरेटर्स वगैरह को वहां पर एक-एक हजार रुपए में रखा गया है, जिसके कारण वे तेल चोरी करते हैं, जिस कारण टॉवर बंद हो जाता है और इस तरह से लोगों को सुविधा नहीं मिल सकती है। मैं मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इन सारी चीजों को हम लोग जब तक नहीं देखेंगे, यह स्थिति सही नहीं हो जाएगी। आज स्थिति यह है कि आप कोई शिकायत कर दीजिए, और आप दो दिन बाद जाकर पूछिए कि हमारा लैंड लाइन सही क्यों नहीं हुआ तथा हमारे मोबाइल में यह प्रोब्लम है, यह क्यों सही नहीं हुई? तो उनके पास सीधा-सीधा जवाब है कि आप की शिकायत आई नहीं है और इसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई ऐसा सिस्टम विकसित हो जाए कि जब उपभोक्ता अपनी कम्प्लेंट करे तो वह रजिस्टर्ड हो जाए तथा उसकी शिकायत पर क्या-क्या काम हुआ, यह सूचना उपभोक्ता को पता चल जाए, जिससे उनको परेशान नहीं होना पड़े। सर, मैं एक और

दूसरी स्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे यहां मोबाइल सैट बाहर से आते हैं और एक बड़ी खतरनाक चीज है, जो चाइनीज मोबाइल आज देश के अंदर फैला पड़ा है, कम पैसे की वजह से इनका एम.आई.ई. नम्बर नहीं है।...(समय की घंटी)...

**सर,** मुझे बोलने दीजिए, साहू साहब दो मिनट लेंगे, मुझे मालूम है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You take only one more minute. Only one minute. साहू जी, आप बैठिए, जब आपका नम्बर आएगा, तब बोलें।

**श्री कमाल अख्तर:** इन पर एम.आई.ई. नम्बर नहीं है। आज अपराधी और आतंकवादी इनका बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके खिलाफ 30 जून, 2009 को एक सर्व्यूलेर के जरिए इसका इस्तेमाल बेन किया गया। लेकिन आज भी पूरे देश के अंदर ऐसे मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इन हैंडसेट्स को बाजार में आने से रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल हैंड सेट की वजह से जो आज विदेशों में करोड़ों रुपया जा रहा है, सरकार को चाहिए कि कोई सस्ता मोबाइल जो एम.आई.ई. नम्बर वाला हो, वह यहां बनाए और गरीब लोगों को जो उससे सुविधा है, वह उसको मिल सके। सर, दूसरी चीज और है।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, please conclude. खत्म करें।...(व्यवधान)... next is Shri Ganga Charan. You should know how to speak within the allotted time.

**श्री कमाल अख्तर:** प्राइवेट ऑपरेटर प्रीपेड और सिम कार्ड वाले मोबाइल कनेक्शन बिना उनकी इंकवायरी किए हुए तथा बिना आई.डी. प्रूफ के उनको दे रहे हैं।...(समय की घंटी)... सर, या तो आप टाइम मत दिया करें या बोलने दिया जाए।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन):** आपकी पार्टी के 13 मिन थे, दो मेम्बर्स को टाइम दिया है, हम क्या करें?...(व्यवधान)... आपकी पार्टी ने दो नाम दिए हैं।

**श्री कमाल अख्तर:** मैं पांच मिनट बोला नहीं, तीन बार घंटी बज गई।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन):** मैं क्या करूँ, बैठिए-बैठिए।

**श्री कमाल अख्तर:** सर, मैं अभी पांच मिनट बोला हूँ।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन):** पांच मिनट नहीं, सात मिनट हो गया है, अब बैठिए।

**श्री कमाल अख्तर:** सर, अब मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। लास्ट में सजेशन देकर दो मिनट में खत्म कर देता हूँ।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन):** बस, हो गया। I called the other Member. ...(व्यवधान)... His time will be deducted.

**श्री राम नारायण साहू:** मैं अपना टाइम नहीं देता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Tiwariji, one second ... (Interruptions)... Tiwariji, I have called the name of other Member. Now, it is not possible.

**श्री कमाल अख्तर:** सर, लास्ट में मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no. I called the next name. Now, it is not possible. You could have intervened earlier. I called him. Now, it is not possible. I cannot help. Once I called the name, then I cannot go back. If I go back, it will be a wrong practice. I



am sorry. I would have considered you. But, I have already called the next name. I am sorry. Now, Shri Ganga Charan. आपका टाइम दस मिनट है।

**श्री गंगा चरण (उत्तर प्रदेश) :** मान्यवर, दस मिनट से पहले disturb मत करिएगा। सर, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के काम पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं दोनों युवा मंत्री श्री ए. राजा और श्री सचिन पायलट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन को भ्रष्ट से भ्रष्टतम विभाग मिला है और इस विभाग को पैसा कमाने की मशीन माना जाता है। हमारे गरीब देश में Information Technology को बढ़ावा देने के नाम पर गरीब की जेब से पैसा निकाला जा रहा है और वह पैसा देश की बड़ी-बड़ी प्राइवेट कम्पनियों की जेब में जा रहा है। बीएसएनएल को साजिशन कमजोर करके, उसके नेटवर्क को वीक करके, प्राइवेट कम्पनियां अपना नेटवर्क अच्छा करके गरीब जनता का पैसा सरकारी खजाने में न जाकर के प्राइवेट कम्पनियों की जेबों में जा रहा है, यह बहुत ही दुःखद है और यह एक साजिश है। यह अच्छी बात है कि गांव-गांव में आज मोबाइल कनेक्शन पहुंच गया है। गांव के किसानों को बिजली, पानी, नहरों और गोदामों की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान न देकर Information Technology को ज्यादा बढ़ावा दिया है। यह एक व्यापार है। पहले गांव के लोगों के पास बहुत पैसा रहता था, लेकिन इसके कारण एक फिजूलखर्ची गांव के लोगों में बढ़ी है। जो टीनऐजर्स हैं, वे इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उनकी जेब में मोबाइल रहता है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज ज्यादातर समय नौजवान छात्रों का मोबाइल पर बातें करने में ही व्यतीत होता है। लड़के-लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि प्यार और मुहब्बत की बातों में कितना पैसा चला जाता है। आज हर पान की दुकान पर मोबाइल कनेक्शन की सिम मिल जाएगी, हर गांव में सिम मिल जाएगी, हर गांव में मोबाइल मिल जाएगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो गांव के लोग हैं, जो गांव के किसान हैं, जो गांव के लड़के-लड़कियां हैं, वहां इसका नेटवर्क फैलाने की क्या जरूरत थी, वहां पर टावर लगाने की क्या जरूरत थी? वहां बिजली का खम्भा नहीं लगा है, गांव में बिजली नहीं है, लेकिन गांव में प्राइवेट कम्पनी के मोबाइल का टावर है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था है, वह मिडल क्लास है। आज मिडल क्लास की कमर टूट रही है, उसकी फिजूलखर्ची बढ़ रही है और इसको रोका जाना चाहिए। जिसे Information Technology की जरूरत है, उसके पास इसको पहुंचाना चाहिए। इसकी बिजनेसमैन को जरूरत है, यह सुविधा उनको उपलब्ध होनी चाहिए। इसके मिसयूज को रोका जाना चाहिए। मैं दोनों युवा मंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि विभाग में जो भ्रष्टाचार है प्राइवेट कम्पनियों के संबंध में, उसको रोकने की जरूरत है। आप बीएसएनएल के नेटवर्क को मजबूत बनाइए। आपने सिमें बांट रखी हैं, जैसा कि अभी हमारे भाई कमाल अख्तर ने कहा कि जब भी फोन मिलाओ नेटवर्क बिजी, नेटवर्क बिजी। अभी हमारे साथी सांसद श्री श्रीराम पाल को जो मोबाइल मिला है, उसमें नेटवर्क ही नहीं है। मैं मंत्री जी से बीएसएनएल का नेटवर्क सुधारने की अपील करता हूँ। आप इसको बेहतर बनाइए। जो spectrum है, उसमें टेंडर पद्धति होनी चाहिए, जो आप फ्रीक्वेंसी देते हैं, उसकी टेंडरिंग होनी चाहिए। इस तरह से उसमें भारी घपला है, घोटाला है। जैसा कि हम सुनते हैं, पॉलिटिकल सर्किल में जैसा माना जाता है कि इस विभाग में जितना पैसा है, जितना घोटाला है, शायद उतना किसी विभाग में नहीं है। आज हमें इससे जितनी फैसेलिटीज हासिल हैं और हम इसको जितना सस्ता करते जा रहे हैं, उतना ही आम जनता की जेब से पैसा निकलता जा रहा है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में तो यह सुविधा भी आ जाएगी कि फ्री में मोबाइल मिलेगा और फ्री में सिम मिलेगी। आप यूज करिए और पैसा जमा करिए। ...**(व्यवधान)**... फ्री में मिलने लगेगा क्योंकि आज इतने पैकेजें आ रहे हैं और इतना कम्पिटेशन है। ...**(व्यवधान)**... इसलिए आज अपराधी लोग भी इसका खूब प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए अपराधियों के ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए। जिस तरह से अपराधियों का नेटवर्क इसका मिसयूज करता है, उसको रोकने की व्यवस्था करने की जरूरत है।

महोदय, उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो BSNL की सुविधा है, वह बहुत ही खराब है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश के लोग BSNL नेटवर्क यूज न करके दूसरी कम्पनियों के नेटवर्क यूज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसके नेटवर्क में सुधार करने की जरूरत है। मैं खासतौर से बुंदेलखंड की बात कर रहा हूं। बुंदेलखंड में इसका नेटवर्क एकदम जीरो है। कहीं-कहीं पर तो इसके सिग्नल ही नहीं आते हैं और लोग दूसरी कम्पनियों, वोडाफोन व हच के नेटवर्क गांव-गांव में फैल गए हैं। इसलिए इसके नेटवर्क को भी गांव-गांव में फैलाने के लिए इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है, चूंकि वह ग्रामीण अंचल है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पहले ये प्राइवेट कम्पनियां कस्टमर्स को ऐसे लुभावने पैकेज देती हैं, जिससे लगेगा कि यह बहुत सस्ता है, लेकिन उसके बाद जो बिल आता है, उसमें कई चीजें, सरचार्ज वगैरह जुड़कर आती हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स के साथ चीटिंग होती है। इस चीटिंग को रोका जाना चाहिए। ये कम्पनियां लुभावने एड देकर कस्टमर्स को आकर्षित करती हैं। वे लुभावने एड एकदम असत्य होते हैं और उसके पीछे कुछ ऐसे शब्द लिख देते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है और कस्टमर्स परेशान होते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दोनों यंग मिनिस्टर्स से यह आशा करूंगा कि वे इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और BSNL के नेटवर्क में सुधार करेंगे। धन्यवाद।

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for having given me the opportunity. Sir, Mark Antony's oration in Julius Caesar is well known — "Friends, Romans and countrymen, lend me your ears, I have come to bury Caesar, not to praise him." I am standing here, today, not to praise the Minister of Communications and Information Technology; that will be taken care of by the ruling front. As a responsible Opposition Party, it is my duty to point out the irregularities committed by the Ministry. Sir, we are discussing the working of this Ministry. A Ministry cannot be separated from the Minister. "यथा राजा तथा प्रजा" First let me take the BSNL. Shri Kamal Akhtar gave a version of the BSNL. हमारे यहां लोग कहते हैं कि BSNL का मतलब है Brother, Sister, Nephew Ltd. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please don't disturb.

DR. V. MAITREYAN: The BSNL is a top-ranking Government employer, next only to the Army and the Railways. Clearly, ensuring its health is very critical to the economic growth, as it contributes nearly Rs. 30,000 crores every year to the Government. The Annual Report of the Department of Telecommunications 2008-09, on page 82, mentions that the BSNL has earned a total revenue of Rs. 38,053 crores in 2007-08 and the profit after tax is Rs. 3,009 crores. The net worth of the company has also increased by Rs. 1,180 crores during the year and reached Rs. 88,128 crores. The BSNL's profit after tax from Rs. 3009 crores in 2007-08 fell sharply to Rs. 104 crores in 2008-09. Since 2006, while the mobile subscriber base grew by 70 per cent, the Mobile revenues showed only a marginal 11 per cent increase. As far as the fixed line revenues are concerned, in the last five years, the BSNL's revenues halved from Rs. 22,814 crores in 2004-05 when the UPA-I took charge to Rs. 11,505 crores in 2008-09 when the UPA-II has now started functioning. This trend is going to plunge the telecom sector into deep trouble. Who is responsible for that, Mr. Minister?

The CAG Report No. CA-25 of 2009-2010 severely castigates the BSNL for the imprudent financial management. It mentions that the BSNL failed to retire Government loan of Rs. 7500 crores in spite of having adequate cash reserves of Rs. 18,829 crores as of March, 2005 parked

in bank deposits with average rate of return of 6.19 to 7.38 per cent per annum as against the rate of interest of 14.50 per cent for the loan. It may be noted that the deposit is parked in the ICICI Bank which has been attracting negative news in the recent couple of months.

Further, you can note that with substantial foreign holding in the ICICI Bank, I fail to understand why the Ministry chose to park its fund in the ICICI Bank, a foreign bank, rather than holding them in any of the nationalized banks. This has a calculated effect of serious subsidizing of the operations of ICICI by the Ministry which is a very serious issue and it reeks of a scam. The CAG Report mentions that the imprudent financial management resulted in excess expenditure of Rs. 1089 crores on interest payment during the period 2005-2007 and the Minister who is accountable for this bungling is your predecessor, who also happens to come from your own Party.

Now, two days ago, we hear from the Telecom Secretary, Mr. Siddharth Behura, that the Government is likely to list BSNL with 10 per cent disinvestment. The timeline obviously will be decided in consultation with the Finance Ministry. Their Department Secretary has gone on record. The BSNL Union observed yesterday, *i.e.*, July 22, as the Anti-Disinvestment Day to protest the Government's selling plan to sell its shares. The BSNL employees Anna Labour Union of my Party, which I preside, will hold massive demonstrations, if the Government goes ahead with its plan of the BSNL disinvestment.

Next, I come to the Spectrum Saga. There have been blatant violations of rules and regulations in the 2G spectrum allocation issue and the role allegedly played by the Telecom Ministry headed by Mr. Andimuthu Raja has come for severe criticism from almost every quarter. I will not go into the details because we have discussed this, time and again, in this House. But I would only like to point out that the Chief Vigilance Commissioner, Shri Pratyush Sinha, in an interview to a newspaper detailed his observations and they are worth mentioning, "We have found that there were gross violations and non-transparent activities in the allocation of 2G spectrum. Basically, the violations are: (1) Granting licences on first-come-first-serve basis; (2) licences being issued in 2008 at prices fixed in 2001; and (3) companies such as Swan and Unitech off-loading their shares at whopping prices to the foreign companies soon after the licences were awarded to them." The CVC said that these steps had led to heavy losses for the national exchequer. Wondering why the Telecom Department had not opted for the auction route, the CVC goes on to say, "The Telecom Department says they had adhered to the TRAI guidelines. We found this version totally wrong. The department had used cherry-picking or pick-and-choose theory to suit their intentions. They selectively picked TRAI recommendations that suited them". This is the CVC's version. Not satisfied with the clarifications and justifications given by the Telecom Department, the CVC said that they are in the process of fixing responsibility. Who is responsible, Mr. Minister?

4.00 P.M.

While CVC is in the process of fixing responsibility, Mr. Raja started his second innings in the Communications and IT Ministry. Two days after he was sworn in, hearing a PIL on the spectrum controversy, the Delhi High Court, on May 29th, gave a certificate to the functioning of the Ministry about which we are talking today. It said, “We are astounded that the spectrum was sold like cinema tickets”. Well done, Mr. Minister! Even in a banana republic, a far lesser indictment would be sufficient to take the severest action against this Minister. Strangely, it is inexplicable as to how Dr. Manmohan Singh feels comfortable whenever the Minister sits in his Cabinet. In the name of competition, new telecom licenses were issued with precious spectrum to inexperienced companies, some of whom are clearly shell out companies, at the cost of global telecom companies. As a result, none of these companies has launched mobile services despite issuance of licences, way back in January, 2008.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Your time is over.

DR. V. MAITREYAN: Sir, I shall take two more minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, take only one more minute.

DR. V. MAITREYAN: Sir, after the 2G spectrum allocation, the Telecom Ministry headed by Mr. Raja landed itself in yet another controversy. Just a month before the Lok Sabha elections, BSNL invited WiMax, High speed internet service, franchise. Of the 11 companies which applied for the BSNL WiMax franchise, as many as five were run by the Minister’s close confidantes. All the five firms were registered on a single date, having the same notary, same auditor, same witnesses and even the same e-mail id. Even the last Annual General Body meetings were held on the same day. What a remarkable coincidence!

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay. Your time is over.

DR. V. MAITREYAN: Sir, there is one more sixth company in this WiMax franchise, Wellcom communications, headed by a man, who is Manager to a person who got anticipatory bail two days ago from the Madras High Court. The circle is full and complete. Fortunately for the department, for the Government and for the country, BSNL cancelled the tender bids after the PMO took note of the issue.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is all. Now, please, take your seat.

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (Tamil Nadu): Sir, he is referring to... *(Interruptions)*... as if he comes from...*(Interruptions)*... What are you talking? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, please. *(Interruptions)*

DR. V. MAITREYAN: Sir, I can go on and on. Then comes the 3G spectrum pan-India licence. The Minister was pitching for a \* low base price of Rs. 2020 crores.

---

\*Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay. Your time is over.  
...(Interruptions)...

DR. V. MAITREYAN: But the UPA-II, now with a comfortable majority, has woken up and has fixed the reserve price for 3G spectrum pan-India licence at Rs. 4040 crores.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Your time is over. ...(Interruptions)... Your time is over, Mr. Maitreyan. What can I do? ...(Interruptions)... Please.

DR. V. MAITREYAN: In all these, the role played by the media and the channels is commendable, particularly, The Pioneer played a crusading role in this. I can go on and on.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Your time is over, Mr. Maitreyan. What can I do? ...(Interruptions)... Please, take your seat. ...(Interruptions)... Take your seat.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, the discussion...(Interruptions)...

DR. V. MAITREYAN: I shall conclude, Sir. The Minister, in an interview to "The Hindu" newspaper said, "I am presiding over a silent revolution in the telecom sector".

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, please. ...(Interruptions)...

DR. V. MAITREYAN: I am concluding, Sir. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, please, take your seat.  
...(Interruptions)...

DR. V. MAITREYAN: Minister Raja, in an interview to newspaper, The Hindu.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, you cannot quote.  
...(Interruptions)... Whatever you quote needs to be authenticated. Don't quote just like that.

DR. V. MAITREYAN: Sir, he himself has said.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is all right. I am not concerned about that. I am only saying that you will have to authenticate whatever you quote.

DR. V. MAITREYAN: Definitely, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay. But your time is over.

DR. V. MAITREYAN: From what can be observed from the statement of the Minister saying, "I am presiding over a silent revolution in the telecom sector." Mr. Raja is not silent, but definitely revolutionary. नाम गुम जाएगा, इनका चेहरा बदल जाएगा, लेकिन राजा की आवाज पहचान है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no. Don't make personal allegations.  
No.

DR. V. MAITREYAN: But I said, Ministry cannot be differentiated from the Minister. I am concluding, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, now please.

**DR. V. MAITREYAN:** नाम गुम जाएगा, इनका चेहरा बदल जाएगा, लेकिन राजा की आवाज पहचान है। People of Tamil Nadu will easily identify his voice, \* ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I shall go through the records in any case. ...*(Interruptions)*... I shall certainly look into the interruptions also.

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे.कुरियन):** श्री महेन्द्र साहनी। आपका समय पांच मिनट है।

**श्री एम. वेंकैया नायडु (कर्नाटक):** आप लोगों को इतना डरा देते हैं।

**उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे.कुरियन):** बात यह है कि even then we will go up to 6.30. Yesterday, I was a little liberal and we went up to 7.30. So, MPs were complaining.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I have one point. Shri Ganga Charan and my other friend were really fascinating. In a normal way, they were actually presenting the functioning of the BSNL and other public sector organisations to bring the common man's sufferings and woes to the House. There is no politics in that. So, we should really have some more time.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It is in your hands. In the BAC, you can ask for more time. Personally, I really feel sad when I stop the hon. Member. But if I have to finish the discussion by 6.30, then I have to stick to time. Yesterday, we were a little liberal. So, we went up to 7.30. I don't want that to happen again. I would suggest, let us raise it in...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It is a good education even for the Minister. There is no politics. They were explaining the practical problems in the field.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Minister has no objection. The objection is from the Chair. I represent the House. I go by your desire and ambition. You desire and I go by that. The House is the master and I am the servant. You decide for it. Now, Shri Sahni.

**श्री महेन्द्र साहनी (बिहार):** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक तरफ मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कुछ खामियां भी हैं। विपक्ष का एक सदस्य होने के नाते मुझे उन खामियों के संबंध में भी कुछ बोलना है। वह खामियां क्या हैं? सबसे पहले इस देश में टेलिफोन हुआ करते थे, तब लोग सीधे इसे टेलिफोन ही कहते थे। हम लोग भी 50-60 वर्ष से इसे टेलिफोन के नाम से ही जानते हैं। आते-आते बाद में उसका नाम बीएसएनएल हो गया और फिर हर जगह बीएसएनएल का बूथ बनने लगा। हर चौक-चौराहे पर, गांव-गांव में बूथ बनने शुरू हो गए। जिस गरीब आदमी का परिवार मुम्बई में रहता था, दिल्ली में रहता था, असम में या कलकत्ता में रहता था या फिर दुबई में रहता था, वह मात्र एक किलोमीटर जाकर पांच रुपये में अपने परिवार से बात कर लेता था। आज उसकी हालत क्या हो गई है? आज मोबाइल क्रांति के कारण हिन्दुस्तान के वह सारे बूथ बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पर हैं। मेरा विचार है कि एक बूथ पर तीन आदमी काम किया करते थे और वह बूथ 24 घंटे खुला रहता था। मेरे पास इसकी संख्या के पूरे आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि देश भर में पांच लाख से कम बूथ नहीं रहे होंगे। अगर एक बूथ पर तीन आदमी काम कर रहे होंगे तो 15 लाख आदमी बेकार हो गए। उन लोगों के लिए आज तक मंत्री महोदय ने अथवा भारत

---

\*Expunged as ordered by the Chair.

सरकार ने क्या सोचा है? इस संबंध में मेरी राय यह है कि अगर आप मोबाइल से इसके पैसे कुछ कम कर दें, तब वे बूथ चल पाएंगे, अन्यथा वह कंप्लीटली बंद हो जाएंगे।

दूसरी बात यह है कि सुदूर देहात में आदमी को पांच, सात या दस किलोमीटर जा करके बात करनी पड़ती है। हालांकि अब मोबाइल है, लेकिन मोबाइल भी वहां सिग्नल्स नहीं पकड़ता है, क्योंकि वहां पर टावर नहीं है। नतीजा यह होता है कि गरीब को वहां से जाना पड़ता है। हम बिहार प्रांत से आते हैं और वहां पर बहुत बड़ा इलाका पिछड़ा हुआ है। मेरा खयाल है कि आज से 30-35 वर्ष पहले वह पिछड़ा राज्य घोषित हुआ। उस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, असम, उड़ीसा, ये सभी पिछड़े राज्य घोषित हुए थे। लेकिन वहाँ पर जहाँ नदी है, उस के पार 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक कहीं भी आपकी लाइन नहीं पहुँच पा रही है। वहाँ लाइन जाती ही नहीं है, यह बात समझ में नहीं आती है। आप और हम क्या कर रहे हैं? इस देश में हम सारे लोग, हर पार्टी के लोग, सिर्फ समाजवाद पर भाषण देते हैं। हर पार्टी के लोग गरीब को उठाना चाहते हैं, बराबरी पर लाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा टीला है, उसको हम थोड़ा ढाह कर के जो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उसको भरना चाहते हैं, लेकिन यह बात हो नहीं रही है। अन्य मामलों पर नहीं, अभी मैं सिर्फ संचार पर कह रहा हूँ।

सर, संचार के मामले में एक बात और मैं आपसे कहता हूँ कि अभी जो लाइन चलती है या जहाँ भी लाइन चल रही है या लाइन अभी लग रही है, उसकी ठेकेदारी कौन लेता है, इसकी जानकारी TAC को नहीं होती है। Telephone Advisory Committee आपकी है, उसको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है कि वह डिपार्टमेंटल होता है या ठेकेदार के माध्यम से होता है। पहले हम लोग जानते थे कि लाइन-मैन की बहाली होती थी। लाइन मैन बहाल हो गया और उसने जाकर के सारा काम कर दिया। जहाँ पर कुछ खराबी है, लाइन मैन को कह दिया कि टेलिफोन ठीक कर दो, तो वह उसे ठीक कर देता था, लेकिन आज उस लाइन मैन का पता ही नहीं चलता है। उस विभाग में कोई लाइन मैन है भी या नहीं, यह पता नहीं चलता है। जनता से डायरेक्ट कनेक्शन जो आपके संचार मंत्रालय का है, इस विभाग का है, उसका एक ही माध्यम है—TAC. TAC की बैठक कब होती है? कभी साल में एक बार या कभी डेढ़ साल पर या कभी बहुत दिनों तक होती ही नहीं है। ऐसे में क्या जानकारी प्राप्त होगी? TAC के मैम्बर जो कुछ बोलना चाहते हैं या जो समझाना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। TAC के मैम्बर को एक टेलिफोन मिला हुआ है, लेकिन उसका फोन महीने में 25 रोज़ खराब ही रहता है। यह क्यों खराब रहता है भई? इसलिए कि पेमेंट उसको नहीं देना है, डिपार्टमेंट को देना है। ऐसी व्यवस्था रखो कि उस पर पैसे खर्च न हों। यह TAC के मैम्बर्स की हालत है।

यहाँ पर हम लोग Members of Parliament बैठे हुए हैं। सारे लोग अच्छे तरीके से यह जानते होंगे कि जब हम मोबाइल से बात कर रहे होते हैं या अपने लैंड लाइन फोन से बात कर रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कि अभी बात कर रहे हैं और अगले सेकंड में वह कट जाएगा। फिर फोन पर बात कीजिए तो वह फिर से कट जाएगा। कहीं बाहर से फोन आएगा, उसे उठाइए तो वह कट जाएगा। यह क्या बात है? यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। पहले यह व्यवस्था थी कि टेलिफोन एक्सचेंज में VIP Telephones की एक लिस्ट होती थी और उसके लिए वहाँ एक स्टाफ रहता था, जो प्रति दिन यह पूछता था कि आपका टेलिफोन ठीक है? तो हम लोग बोल देते थे कि हाँ ठीक है, तब वह संतुष्ट हो जाता था। लेकिन, आज वह हालत नहीं है। आज इस पूरे देश में खास करके जिसके लिए...(समय की घंटी)... हम सब लोग समाजवाद पर भाषण देते हैं, उस इलाके में इस मामले में— ऐसा तो सभी मामले में है, लेकिन इस मामले में— बहुत अंधेरा छाया हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि—

छाया है अंधियारा, उजाला होना चाहिए।

हर गरीब के हाथ में, मोबाइल जाना चाहिए।

**श्री आर.सी. सिंह** (पश्चिमी बंगाल): सर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे संचार और सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यकलापों पर बोलने का अवसर दिया है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि संचार और सूचना-प्रौद्योगिकी विभाग एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी के बिना संचार का इतना विकास नहीं हो सकता था, जितना कि पिछले कुछ वर्षों में हमने हासिल किया गया है।

सर, पहले मैं संचार के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण विधा है, जिसके बिना न तो हमारी rapid growth हो सकती है और न ही हमारी अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर्स का modernization हो सकता है। यह सत्य है कि सरकार ने 1994 में National Telecom Policy, 1999 में New Telecom Policy और 2004 में Broadband Policy बनाई। इसके अलावा भी उसने और कई initiatives लिये। इसमें कोई दो राय नहीं है कि National Telecom Policy के जरिये DoT के काम को आगे बढ़ाने के लिए private partnership की कल्पना की गई है। सर, प्राइवेट प्लेयर्स DoT के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक बनने के बजाय, DoT के अधिकारियों की मिली-भगत से DoT को चूना लगा रहे हैं। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा टेलिकॉम नेटवर्क दुनिया में third largest और वायरलेस नेटवर्क दुनिया में दूसरे स्थान पर है, लेकिन अगर आप हमारे देश की tele density को देखें, विशेषकर रूरल density को तो यह वैसी नहीं है, जैसी कि हमें उम्मीद थी। हम ने सोचा था कि प्राइवेट प्लेयर्स आने के बाद रूरल एरियाज में tele density बढ़ेगी, लेकिन हम जानते हैं कि प्राइवेट कंपनीज का काम केवल मुनाफा कमाना होता है, सोशल obligations को पूरा करने में उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं होती है। सर, आप अर्बन density को देखें, यह 88.94 है 100 की आबादी पर, जबकि रूरल density मात्र 15.18 है और यह 15 भी पी.एस.यूज. के द्वारा ही कवर की जाती है। प्राइवेट टेलिकॉम प्लेयर्स इसे मांगते नहीं हैं, उधर उनका ध्यान नहीं है। वे वहां जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए सरकार को strict guidelines बनानी चाहिए, instructions देनी चाहिए कि वे tele density का 40 परसेंट रूरल एरियाज में दें। तभी हम अपनी रूरल एरिया density को बढ़ा सकते हैं।

सर, मेरा दूसरा पॉइंट टेलिकॉम की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ये latest technology, manpower, जिसमें infrastructure मौजूद है, लेकिन आप अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज की ग्रोथ को देखें तो पाएंगे कि यह केवल 20 परसेंट है, वहीं पर प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ 80 परसेंट है। इस के पीछे क्या कारण है, इसकी तरफ मंत्री जी को जरूर ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के पास अच्छा infrastructure, technology और manpower नहीं है। सर, आप एक बात और देखेंगे कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, उनकी कोई proper wage भी नहीं है। मुनाफा कमाए चले जा रहे हैं। इन के ऊपर सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं लगायी गयी है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वह टारगेट फिक्स करें और पब्लिक सेक्टर के अधिकारियों को काम करने की स्वायत्तता दें और result दिखाने को प्रेरित करें जिससे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ compete कर पाए।

सर, इकॉनॉमिक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि 73 परसेंट से ज्यादा लोग 20 रुपए से कम पर अपना जीवन-यापन करते हैं। दूसरी ओर अपने यहां ऐसे भी लोग हैं जो अनुचित तरीके से अथाह धन कमा रहे हैं। इसलिए देश के विकास में जो त्वरित गति आनी चाहिए थी, वह नहीं आ पा रही है बल्कि असमानता बढ़ रही है। यह गरीब लोगों में निराशा व क्षोभ पैदा कर रहा है। मुझे इस बात की आशंका है कि सरकार की ओर से जो inclusive growth की बात कही जा रही है, उसमें गरीबों की जिंदगी में आशा की किरण पैदा होती नहीं दिखायी पड़ रही है। सर, इस संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा कि इनके यहां employment में Scheduled castes के 19.24 परसेंट, Scheduled tribes के 06.89 परसेंट और Women की 14.13 परसेंट भागीदारी है जोकि बहुत ही कम है। इस तरह इनके लिए employment के और ज्यादा अवसर दिए जा सकें जिससे कि देश के डवलपमेंट में वे अपना योगदान बढ़ा सकें। सर, इस में बहुत से लोग Scheduled tribes के इलाके से हैं, जहां काम शुरू होता है, उन्हें वहां मौका दिया जाए ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सके।



सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि रूरल, हिली और इंटीरियर एरियाज में जो पी.सी.ओज. थे, उनमें अभी जैसे कि एक माननीय सदस्य ने कहा ...(समय की घंटी)... सर मैं पांच मिनट में सिर्फ पॉइंट बोल दूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You have already taken five minutes.

**श्री आर.सी. सिंह:** सर, दो मिनट में खत्म कर दूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Take one minute more.

**श्री आर.सी. सिंह :** सर, उसमें लाखों लोग काम करते थे, लेकिन उनमें तीन लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। उन्हें दोबारा नौकरी मुहैया करायी जा सके, इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए।

सर, मेरा दूसरा पॉइंट fund utilisation के बारे में है। इस बारे में एक साथी पहले ही बोल चुके हैं, इसलिए मैं उस के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस फंड का मात्र 27 परसेंट utilisation हो सका है, इसे त्वरित गति से किया जाना चाहिए। इस बारे में TRAI ने भी कहा है।

सर, पोस्ट ऑफिसेस की तरफ मैं सिर्फ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देश में डेढ़ लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस हैं और ये “बाबा आदम” के जमाने के बने हुए हैं। उनका modernisation नहीं हो रहा है। उन्हें इंटरनेट फेसिलिटी देने की बात की गयी थी, वह भी उन्हें मुहैया नहीं हुई है। इसमें जो काम करने वाले हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा नहीं के बराबर है...(व्यवधान)... इनका standard बढ़ाया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, okay. That's all.

**श्री आर.सी. सिंह:** ठीक है, सर। मैं केवल points बोल रहा हूँ और कोई बात नहीं कर रहा हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no. I cannot allow more time.

**श्री आर.सी. सिंह:** इनको modernize किया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Everybody wants to take more time. What can I do? Please cooperate.

**श्री आर.सी. सिंह:** श्री-जी आदि के बारे में बोलने का समय ही नहीं मिला। थैंक यू सर।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you very much for cooperation. Now, Dr. Chandan Mitra. Why I am doing this is, otherwise, we will have to sit beyond 7.00 p.m. That is the problem. At least by 7.00 p.m. we should conclude it.

DR. CHANDAN MITRA (Nominated): Thank you Mr. Vice Chairman.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I hope you know how much time you have got.

DR. CHANDAN MITRA: You said nine minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes. Please continue.

DR. CHANDAN MITRA: Sir, I rise first to congratulate the Prime Minister for the appointment of a very young and competent Minister of State in this Ministry. I hope his presence is going to act as a check and balance to a Department that has otherwise been encircled by scams and adverse reporting in the media.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Insinuation is not permitted.

DR. CHANDAN MITRA: Sir, I have not insinuated. I have only congratulated the Prime Minister for the appointment of the Minister of State.

Sir, I will first start with the Department of Posts. Just to express certain concerns, according to the Economic Survey of 2008-09, at present, in India, one post office serves 7,174 persons and covers an area of approximately 21.12 square kilometers. On 19th of February 2009, in a reply to a question in this House, the previous Minister of State had clarified that the norms for opening a post office in India in normal areas is a population of 3,000 and in hilly, tribal, desert and inaccessible areas, a population of 500. Now, if this is the gap, from 7,174 people at present if you want to bring it down to 3,000 people, Sir, I would expect that the Government would make adequate provision in the Budget so that this target can at least be brought as close to realisation as possible. But if I may read from the notes on the Demands for Grants of the Budget presented by the Finance Minister, Sir, point no. 4, page no. 37 of the Expenditure Budget, 2009-10 says, "This year's Budget for expenditure provides for normal growth and expansion of Postal Services. The emphasis of the Plan activities is on all round development and repositioning of India Post through technology induction and entrepreneurial management, etc". But no provision whatsoever has been made for increasing the number of post offices to bring down the density from 7,174 to 3,000, which is the target. Sir, that is my first point.

This kind of callousness pervades all other areas of this Ministry. on tele density, the Government has patted itself on the back in the Economic Survey of 2008-09 by saying that total tele density increased from 12.7 per cent to 35.65 per cent. Very impressive, Sir. But, come to the next figure. Rural tele density reached 13.81 per cent in January 2009. That is the rural tele density. But the target is to have 25 per cent tele density by the end of the Eleventh Plan. Where is the provision for increasing rural tele density? What steps are being taken to increase the rural tele density and bridge this yawning gap between rural tele density and urban tele density?

Sir, one reason why tele density has not gone up sufficiently brings me to a point which has been mentioned in this House earlier and today very eloquently by my friend, Dr. Maitreya, is the issue of spectrum allotment. Today, the 2G spectrum allotment has been made but has not been operationalised. Why? Because there is a big question mark on the 3G Spectrum allotment. Now till the 3G Spectrum allotment issue is sorted out, the operationalisation of 2G Spectrum is held over. The growth of teledensity, which is the objective of the Government, is being held over and why? Because there are such serious allegations of malpractice in the entire allotment.

On 3G Spectrum alone, let me point out that, I think, on 18th June, the Group of Ministers fixed the reserved price of 3G Spectrum at Rs. 4,040 crore, which is double of what was proposed by the Ministry. Sir, this is a very serious matter that the Ministry undervalues its own product to such a point that the Group of Ministers had to intervene and double the fixed

reserved price for the allotment. Incidentally, the proposal of the Ministry was Rs. 1,010 crore as the basic price of broadband wireline access which the Group of Ministers hiked to Rs. 2,020 crore.

Clearly, that is the undervaluation by as much as 100 per cent in both the 3G Spectrum and broadband wireless service. It is a very serious issue. I say that this is linked with the Budget, because on this depends how far and how fast your teledensity can be increased. I do not want to go into the details of the 2G Spectrum scam which has been discussed at great length. But I think that it is a matter of \* .

It was widely reported and widely criticised in newspapers. 'License for a killing' and things like that were making headlines. I am not talking about my paper. I am talking about other papers which used that kind of terms. There is yet no resolution of the issue.

The fact is that it was sold on a first-come-first-served basis to various people who bought the Spectrum at a throwaway price. One company bought it for Rs. 1,537 crore through the dubious first-come-first-served basis and sold 45 per cent of its shares to a UAE-based firm in September, 2008 at Rs. 4,500 crore.

Just ten days prior to that deal with the UAE company, BSNL signed an unprecedented confidential deal with the original company, the buyer of the spectrum, allowing it to use BSNL's communications network in the entire country without specifying the call charge. The BSNL proposed the charge of 52 paise per call, but that was removed from the MoU which was signed.

Subsequently, of course, because of the CVC's intervention that had been stopped. But such has been the activity of the Ministry. How can we trust and have any faith in it? The CVC says that this Ministry has caused the exchequer a loss of Rs. One lakh crore. How can we believe or depend on any of the plans that have been submitted by it and for which the Government is seeking the approval of the House to spend this money?

The reserves of the BSNL, with whom this deal was signed, rose from Rs. 18,829 crore in March 2005 to Rs. 35,953 crore in March, 2007. Yet it did not return Rs. 7,500 crore it had taken as Government loan in April, 2005. The CAG has commented very adversely on this excess expenditure. The expenditure incurred as a result of this financial malpractice is Rs. 1,089 crore.

I have really nothing more to add to it. What I have said very clearly shows that the Ministry, which is supposed to be a national asset of the country, which has the best of engineers and the best of technologies, is incurring huge losses in various operations and things are being undersold in a manner that is \*, to say the least. Therefore, I think that the demand for further investigation into this episode is obvious before this House approves of the budget.

Finally, I would like to join a large number of hon. Members who have talked about the really shoddy services of the BSNL in the whole country. Sir, I remember an old song which goes like this. मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलिफोन, तुम्हारी याद सताती है। People could call and speak

---

\*Expunged as ordered by the Chair.

from Rangoon 50 years ago. Today, if you want to speak from Rajpath, you can't speak to Janpath. From Janpath, you can't speak to Shantipath. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you for sticking to the time. Now, Shri Rajeev Chandrasekhar. ...*(Interruptions)*... You have ten minutes.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (Karnataka): Thank you, Sir, for letting me speak on the working of the Ministry of Telecom and Information Technology.

Sir, I will restrict my discussion to the telecom sector in India because that is an area in which I have a little bit experience and exposure. Sir, it has the third largest telecom network in the world with 273 million connections. The gross revenues for the sector have grown to Rs. 1,30,000 crore which account for three per cent of the GDP of the country. Most importantly, Sir, this rapid growth in the telecom network has resulted in an overall teledensity of over 33 per cent.

The opening up of the telecom sector has led to large inflows of investment in an economy that has been investment-led. But, Sir, the success of the telecom sector over the last decade do hide the fact that there are major disfunctionalities that have crept into the sector over the last few years in particular. Most of us are aware of the controversies and questions raised about issues like spectrum allocation, mobile licensing, service provider distinction, illegal international calls, etc. that have been raised in Parliament and outside many, many times over the past years.

Sir, to start with, I would urge upon the Minister and the Ministry to establish a fresh, open, credible and transparent approach this year and going to the next four years. I would strongly recommend that for the first time a clear set of outcomes be defined, if necessary, with a New Telecom Policy that supersedes the NTP of 1999. Ten years on, there is a strong argument for a New Telecom Policy that reviews the sector and lays out these new targets and addresses the disfunctionalities that have crept in over the last decade.

Sir, let me make a few suggestions for the Telecom Minister and the Ministry going forward. Sir, the first issue is of sustained affordability. Sir, it is a widely known fact that there is considerable price and other forms of cartelisation widely prevalent in the telecom sector. Both the regulator and the Department have failed completely in the task of creating true competition in this sector. This is an important issue that needs to be fixed. Indeed, I have the misfortune of listening to one regulator referring to cartelisation as cooperative pricing.

Sir, the fundamental obligation of the Government must be to ensure a framework of sustained consumer benefit. The only way to ensure this is to ensure intense and sustainable competition in the sector by way of various technology options and service providers. This must be kept in mind and I am glad that the Minister has agreed to introducing multiple 3G licences

through auctions that will increase the competition in this sector. But, if he is genuinely serious about competition, then, he cannot leave unattended the critical issue of VOIP recommendations by the regulator that are gathering dust in the DoT. Implementing VOIP is the best way to ensure reduction in prices and allowing a totally new category of inexpensive voice services especially for rural and poor sections of society. The reasons for inaction on introducing VOIP seem to be at the behest of some lobby or the other, and public policy-making cannot and should not be directed by these lobbies. It will be difficult for him to justify why the commercial interests of some of the richest companies in the country would come in the way of implementing a policy-decision that is universally known to reduce tariffs and especially benefit the rural folk.

Sir, the second issue is of quality which has been discussed by some of my colleagues. While we celebrate the significant progress in teledensity in our country and attribute it as a success of the policy, as we should, the significant gap in this is the issue of consumer quality and the quality of network. This is an area where our service providers, both public and private, have neither paid enough attention nor has the Government. For too long, service providers, both private and public, have been allowed to escape from being accountable for this and not making the capacity investments required for it. I have heard many times the reason given as spectrum shortage. That is clearly a solution that is to save operators from investing an additional capital expenditure. Sir, this is a serious issue and, indeed, one of the blights on the, otherwise, bright picture of Indian Telecom. I would request that the Department under the Ministry should make this an area of focus and ensure that the Operators make the investments and operate at a set down threshold of service and network quality and the Regulator conducts quarterly or half-yearly audits with severe penalties for those who fail the standards of quality.

Sir, third is the issue of choice. Sir, as you know, currently, once a customer gets his telephone number, he is stuck with that operator, good or bad, and can only migrate by changing his number. The need to surrender his number and move to a new number is a significant exit barrier for the customer and is an incentive for the operator to provide a sub-standard service. The decision of the Government of Telecom Number Portability will change the centre of gravity from the Operator to the consumer. I would urge the Department to ensure that the implementation of this is expedited and launched this year itself.

Sir, if the Department and the Government is serious about creating a public policy framework that places the citizen and customer at the centre of its policy making, these three issues of delivering competition, choice and quality are critical and non-negotiable. Implementing these three will truly place the consumer at the heart of Government policy-making.

Sir, fourth is the issue of serving more rural India. Successive Governments have accepted that this is a sector that has performed well, but for the rural India, which has been an area of

serious challenge, even today, Sir, while three out of every four urban Indians have access to telephony, in rural India, the number drops to one out of ten. This digital divide is having a serious multiplier effect in holding back socioeconomic growth, especially when, as we all know, 70 per cent of India still lives in the rural heartland. Lack of connectivity and affordable options are, both, major deterrents for rural India to catch up with the progress that you see in urban, and semi-urban cities. I would urge a focussed strategy of incentives and SOPs to accelerate investments into rural markets, combined with a more aggressive use of the U.S.O. Fund with a target for rural teledensity, which is three out of ten, by the end of these five years.

Sir, the fifth, and the most important issue, is the issue of institutional and regulatory performance. As someone who has intimately lived the highs and lows of the Telecom sector from the day it was first opened up to competition, I must say, Sir, that one of the biggest disappointments around the sector is its continued ambiguity on what should be a relatively straight-forward process of auctioning spectrum. To avoid any further controversies and allegations of bias, it is important that all future allocations of spectrum for existing licensees and new licensees should be only through auctions, and these controversies should be put to rest. I have written to the Minister, earlier, on this issue, and he has assured me that this will be the case. I look forward to his confirmation of this during this debate.

Sir, while the TRAI Act was enacted in 1997 and amended in 1998 by Parliament, it was done to assure an era of transparency and accountability. Sadly, the performance of the TRAI has been patchy and highly inconsistent and, there, I say, Sir, sometimes, very questionable. I believe it is time for a complete review of the TRAI Act and associated Government policies. Unfortunately, the TRAI Act amendment, in the last Session, was rushed through without a debate. But that would have been a good opportunity for a discussion on the TRAI Act amendment.

Let me quickly lay out some points in the TRAI Act amendment, Sir. There is a greater need for the TRAI to enhance its accountability. Currently, the TRAI seems to be accountable to no one. There is no structure through which the TRAI can be held accountable to Parliament.

Sir, TRAI reports to Parliament through MOC&IT, but, is, usually, in conflict with the Ministry because its recommendations are either rejected, modified or plain, simply delayed. TRAI, that is subservient to the Ministry and often staffed by retired bureaucrats from the Ministry, is clearly losing its sense of independent objectivity.

Sir, some colleagues of mine have mentioned this point, but I need to repeat it. The Government seems to cherry pick sections of the TRAI recommendations or interpret them differently or partly implement them, depending upon its convenience and comfort. In doing so, it is refusing to recognise the inter-linkages between a comprehensive set of recommendations

and may accept recommendations, in part, which do not meet the policy objectives or transparency test that is necessary for the functioning of the telecom sector and its policy making. For instance, it accepts TRAI recommendations for distribution of spectrum, but refuses to accept the process through which the market value needs to be determined. This has been the problem which led to a major confusion in the last spectrum allocation process. Checks and balances need to be built in the system wherein TRAI recommendations are either accepted or rejected in totality or if they are modified in part, then that should be with the consent of the TRAI rather than cherry picking.

Sir, on the second point, there is no time-limit with regard to how long the Government can wait or delay the implementation of TRAI's recommendations. When the Government finds it appropriate, it implements the recommendations within weeks. In other cases, the recommendations have been pending for 2-3 years. It is necessary that the Ministry and the DoT self-regulate themselves or eclipse themselves under some sort of legislative amendment wherein they need to respond within a given a period of time, say, 60 days, to a recommendation of the TRAI by either accepting or rejecting or returning to the TRAI with modifications. This will ensure that policy making is timely and decisions are not caught up in bureaucratic delays, and this will also ensure, most importantly, transparency in DoT's response to TRAI's recommendations.

Sir, a few quick words about the TEC. The TEC needs to largely upgrade its technical capabilities to ensure that they are in keeping with the latest state-of-the-art technological developments in the telecom business. I think, that is an important area for the years to come. ...*(Time-bell)*... I am just finishing, Sir.

Sir, the telecom sector is a great example of infrastructure development with little or no investment by the Government. These policy moves, coupled with the significant headroom for growth, will make India the most vibrant and exciting telecom destination in the world for investors. I look forward to hear the Government's response to my suggestions. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Mr. Rajeev Chandrasekhar. Shri Arun Jaitley, the Leader of the Opposition.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Mr. Vice-Chairman, Sir, when we are discussing the working of the IT and Telecom Ministries, let me first start with a positive note. I start with a positive note because since the mid nineties or since 1995, when we opened up these sectors, if we look back over the 14 odd years, there are a lot of positive and good things for India. This is the one sector which can be genuinely termed a big success story. From a situation where we had poor quality services and people were denied telecommunication services — I remember when the opening up took place, India's tele density was less than one per cent — after 14 years, today we have reached a stage where we have 15 per cent in the rural areas and 88 per cent in the urban areas. The total tele density is about 35 per cent. In 14 years,

we have actually grown from one per cent to thirty-five per cent tele density which is something that we had not imagined at that time. The line-man who used to be a very important man in our lives suddenly started slowly disappearing from our lives. But this is a good news, as far as the telecom services are concerned. We are also providing the cheapest telecommunication services in the world. Therefore, I don't think we can be cynical or overcritical about the overall picture of the sector. It is a big success story.

Having said about this positive aspect, there is one area of concern and, in fact, an area of worry. That area of concern and worry is the private sector — which has been encouraged and which has in many ways done a commendable job in providing good and cheap services — has also become very large and powerful. Therefore, the influence of this sector on decision-making and the influence on decision-making through collateral reasons is becoming very large, and as a result of which all these controversies that we hear continuously about the sector and they are disturbing. Now, this may relate to the function of the institutions within the Ministry, etc. But this is something which we are really concerned about. There is one area which has been referred to by some hon. Members, and I just want to confine myself to that one area — Dr. Chandan Mitra, after that Shri Rajeev Chandrasekhar and earlier Dr. Maitreyan also referred to it — that is, the manner in which the privileges are being conferred on individual corporate houses by the Government. This manner has to be fair. The essence of free trade can survive only if it is fair trade. If it is not fair trade and if there is some kind of a conduct which is undertaken in this trade and which raises serious doubt, then the credibility of the whole system goes down. The Finance Minister, in this Session, presented the Budget. Sir, this House, as also the other House, and the whole country had a unanimous concern on one issue, and that is, about the fiscal deficit which was 6.8 per cent. And, if the fiscal deficit at 6.8 per cent had to be corrected in the next year, various methodologies were suggested. And, one of the measures taken was, and I think, that is the correct thing, which the hon. Prime Minister has done, — we would stand by the Government if it implements that policy — he said, We have constituted a GoM under Shri Pranab Mukherjee. The GoM would now supervise the entire 3G auction, and we are expecting to raise, through the market mechanism of public auction, a large consideration, which the Government fixed at about Rs. 35,000 crores. And the Government said that a part of the fiscal deficit in the coming year would be corrected through this mechanism of public auction as far as the spectrum is concerned. And, through the 3G auction, if the Government is able to raise Rs. 35,000 crores, which I do hope that it is able to raise, then, perhaps, we can have this one area of concern being addressed. But, then, what is the price that we have already paid as a country for this wise counsel to prevail that we need a GoM under the Finance Minister; that we must auction, fix a base price, and then, a public asset, which is a scarce asset, that is, the spectrum, must get us the highest bidding value? What did we do in the last round? References



were made, but let us just dissect what we did in the last round. I do not want to get into individuals or companies or Minister or any officer for that because I am really concerned with the system that we have followed. The first thing we did was, when we decided an Open Licence Policy in 2007, we fixed a date, and the date we fixed was 1st of October, 2007, whereby anybody could come and apply for a licence. And, once you get a licence, the licence is a piece of paper which means nothing unless the licence is accompanied by a spectrum allocation which will entitle you to operate the service, and then, you operate your service. While analysing those applications, we suddenly decided that 1st October post-facto would become 25th September; we cut it short by five days.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.)

Now, what happened? We found a large number of players, who had applied earlier in point of time, when we read their names, were real estate players; so, the real estate entering into telecom! And a number of international, globally experienced players, who would have come after 25th, got knocked out. The Court has now commented that the rules of the game were changed after the game was being played. So, you had inexperienced players who, in the first-come-first-serve, stood ahead, and then, you suddenly had a number of internationally experienced players, who were out. Fair enough; these gentlemen were allotted. We are not concerned whether experience comes in, or, inexperience comes in. You allot them the spectrum. So, the question arises: How did you allot those spectrums? What the Government is doing today, and a very wise decision by the hon. Prime Minister is, he constitutes a GoM, — after all, this is an asset, worth thousands and lakhs of crores of rupees, being auctioned — puts a senior Minister of high credibility like the Finance Minister as the Chairman, auction it; let them supervise the criteria, and whoever pays the best with the requisite credentials gets it. What we did was, we fixed a value of about Rs. 1,650 crores. How did we, in 2007-08, arrive at this value of Rs. 1,650 crores? If you remember, the initial opening out of the telecom sector was in 1995. The second round players came in 2001. In 2001, there was some auction. So, the market determined what the fourth player in that auction had given. Now that had become a price for being applied in 2001-03 because that was the market-determined price for it. That price, blindly, is fixed as the 2007-08 price. The market has undergone a huge change between 2001, 2003 and 2007. Even if a simple accounting system of updating the value to a net present value is taken between 2003 and 2007, thousands of crores would have changed. The telecom market has expanded. So, you allot it to about nine players at Rs. 1650 crores each. Now, all these players have a share-company, one company. An application was allowed a spectrum worth Rs. 1650 crores. When they get this, what is the value in the market? The FDI limit in telecom is 74 per cent. So, every player who gets this can now take a foreign collaborator. He can take a foreign collaborator with 51 per cent, 49 per cent, sixty per cent, up to 74 per cent. Now, some of them slowly started getting foreign collaborators and they started handing over

the control which effectively goes to the collaborator. Now, transactions with foreign collaborators took place. Three of them did a public transaction and there is nothing illegal about that transaction because the FDI policy allows 74 per cent. You paid Rs. 1650 crores and upon getting that Rs. 1650 crores worth of assets, overnight the value was two billion dollars, more than Rs. 9000 crores. So, each company which bought that spectrum in 2007-08 at 2001 prices, the 2007-08 value became nine to ten thousand crores, that is, two billion dollars. They could not sell hundred per cent; so, if you sold 74 per cent, you got 74 per cent of approximately two billion dollars; if you sold 60 per cent, you got 60 per cent of approximately two billion dollars and so on. As I said, there were players from real estate and other markets; each one of them had a company, applied for spectrum, got a license, got a majority player from a foreign country, transferred it to him and Rs. 1650 crores became nine to ten thousand crores. Now, if in each case, the difference is that of six to seven thousand crores, for nine players what is the difference? The value goes well into sixty thousand crores plus. Now, you have spectrum as an asset being given in 2007-08; they did not have a single telecom subscriber. They had a company and spectrum and Rs. 1650 crores became two billion dollars, Rs. 60000 crores; it could be fifty, sixty or seventy; the valuations can vary depending upon how you get the collaborator. Now we come back the question: should this have been given at the earlier prices or should there have been an auction? I can understand compulsions of coalition politics. And this is one case where compulsions of coalition politics have cost the country. I see many eminent Members from the ruling party sitting here; please make back-of-the-envelope calculations; if the spectrum had been auctioned and not allotted, this 6.8 per cent fiscal deficit, probably, would have been five per cent or less. There hasn't been a bigger national loot than this! And now you become wiser and Mr. Pranab Mukherjee says that the 3G spectrum will not to be allotted like this; it will be allotted in a manner that we will fix the base price — the base price being mentioned in the newspapers is Rs. 4040 crores — and then the auction will take place; you may get five thousand or six thousand crores, whatever is the value. Now, this is the whole case.

Sir, I only feel, for 3G, the Government apparently has corrected itself; it has learnt a lesson. And I have no hesitation in saying that it is a sensible thing that the Government is doing. What do we do about what happened in 2G. It is a closed transaction; it is a concluded transaction. Somebody — whoever; whether it is the TRAI or some officer in the Department who has managed it; you sell a plot of land for less than the market value in the Urban Development Ministry, the officer responsible in any development authority will be held liable. You have caused unfair gain to the private party and a loss to the Government; an unfair loss to the Government and an unfair gain to the private party. It is a prosecutable offence under section 13 (1)(d) of the...*(Interruptions)*...

5.00 P.M.

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI A. RAJA): One minute, Sir. I have high regards for Shri Arun Jaitleyji. He is putting up a very good argument, which seems to be very legitimate. But, before his arguments, I want to submit that certain things must be apprised to him. Thereafter, he is entitled to make his arguments. I referred the matter regarding 3G to the Group of Ministers. Of course, this is a small intervention, and I do not want to take much time of the House. The base price was not decided by me or by the Ministry. It was recommended by the TRAI, Rs. 1,000 crores; it was doubled in the Telecom Commission, Rs. 2,000 crores; again, it was doubled by the Finance Ministry, Rs. 4,000 crores. I had a lot of confusion in terms of number of slots, base price, and I referred the matter to the Group of Ministers. I referred the matter to CCEA. But, I would like to say one thing that there is a distinction between 2G and 3G. Sir, 2G is intended for the benefit of the consumer; 3G is a value-added service. That is why you prepared a statement, you devised a document in the name of NTP-99. 2G is for the common man. A person who is vending vegetables in common streets must have a telephone, for which the spectrum cannot be auctioned for Rs. 60,000 crores. 3G is a value-added service. So, the TRAI put a very categorical demarcation by saying that 2G is a basic service, it cannot be auctioned, it should go for robust circulation; and 3G is a value-added service, so you go in for auction. That is not my decision. I can put it otherwise. ...*(Interruptions)*... You must have the patience. See, the logic is — I can tell the logic — subsidy can be provided to rice, which is intended for the common people, but you cannot compel the Government to give subsidy for ghee. So, the hon. senior Member must keep this distinction in his mind that 2G is something different and 3G is something different. This difference was drawn by the TRAI, not by Raja or not by the Prime Minister. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I have great affection for my learned friend, the hon. Minister, Mr. Raja. He is a very competent Minister, and I have no personal agenda or any other political agenda on this issue. I have no difficulty in accepting his arguments. I preface it by saying, we opened this sector and the sector is a success story. But, let this success story not be clouded by the influence of this sector on decision-making. I have, Sir, no difficulty in accepting, we had also been in Government, I had been associated when we were in the Government with various Groups of Ministers which were working on this subject, the GoTIT, the GoM...*(Interruptions)*... And on that functioning, now the Minister wants to take the credit that he referred it to the 3G, GoM, I stand corrected, I will give him full credit for it. I have no difficulty with 3G. But the difficulty today is, we should have considered the policy of auctioning this asset. If the private sector can take this asset from you and effectively auction it the next day, why should you not have auctioned it in the first instance? ...*(Interruptions)*... This is the point. When the private sector can transfer 60 per cent or 74 per cent of these holdings within days of taking the spectrum and the licence from you, and Rs. 1650 crores become two billion dollars, why should

the Government of India have not done it? If the Government of India had done it, this enrichment which has gone into the pockets of the private sector would have gone into the pockets of the Government and this 6.8 per cent fiscal deficit would have, as I said, been much lesser. That is all I have to say. Therefore, please ask the CVC, ask other investigating agencies who is responsible for ill-advising the Government to go in for this policy which has caused wrongful loss to the Government of India and a gain to the private parties. I am conscious of the fact that it is difficult to reverse transactions, which are concluded. But then somebody has to be held accountable. As I said, these are all prosecutable offences. Therefore, this matter must be gone into the depth. We have learnt a lesson and we are correcting ourselves from 3G but then one of the arguments...*(Interruptions)*...

SHRI A. RAJA: Sir, it is not a question of learning. Two categories are separate and distinct. Please do not have specifications in it. This is my humble submission. You should not have confusion between the two things. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, leave it. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, the two categories are separate but let us not forget one fact that spectrum is an asset which is a common factor. Secondly, the companies are operating it; let us not shed now crocodile tears for the consumer. The consumer has not got a single service; there is no single telecom connection, which has been granted after these auctions. ...*(Interruptions)*... The obligation is three years. This has now been traded by the recipients of these licences by giving it to somebody else. All that I am saying is, Sir, it is a serious mistake, which has been committed. And, therefore, while we are correcting it for the future, there should be some responsibility fixation for the past and it must take place when we discuss the performance of the Telecommunications and IT Ministry. That is all I have to say, Sir. Thank you.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Thank you, Sir. The debate was more or less focussed on the latest value addition in the Department of Communications. But we have totally forgotten that a Postal Department is also there which has 1,62,976 people working for it. Out of this, 40,003 are Scheduled Caste, 15,455 are the Scheduled Tribes, and 30,630 are women employees. Through this human resource for the last 154 years, the Postal Department is working and serving the common man in the villages and also the urban slums. The number of post offices in the rural areas is 1,39,173 and this number is 15,862 in the urban areas. Actually when we go through the statistics, we see that gradually this Department and also its branches are going down. In 2007-08 itself, the number of post offices in the rural areas was 1,39,149. In 2003-04 the urban areas were catered by 16,520 post offices. Now it has come down gradually due to the other means of communication created by the private sector, and they are becoming rich by providing this service. At the same time, we are doing the other important service of small savings through which a large number of people are getting

employment as agents. Sir, the State Governments were very much interested in having many savings accounts and money to show in order to get more funds from the Planning Commission at the time of getting allotment from the Central Government. But now-a-days they are also not interested. At the same time, from the calculations done by the Department, the income through these saving banks alone is coming around Rs. 3455 crores. The expenditure is Rs. 213 crores for the employees and other services. Here I would like to draw the attention of the Department that this is a common man's saving, savings of the widows who are saving Rs. 200, Rs. 500, or Rs. 30 per month. In that way, they are saving to the tune of Rs. 10,000 or Rs. 15,000. The agents who are getting a small commission are going to the doors of that particular small man to collect and they deposit it in the post offices. They get a small amount as commission. Unfortunately, three years ago in the Budget, that commission was also reduced and the bonus was also totally taken away in the pretext that the small savings account is not needed so much for the State Government or the Central Government programmes because IMF and the World Bank are ready to give for less interest compared to this particular interest. Sir, I would like to draw the attention of the Government that this Government is for the *Aam Aadmi*. Therefore, we have to protect the small savings people who are dependent upon the Government rather than going to the private sector and moneylenders. Therefore, this aspect of giving one per cent more than the normal interest not only for the PF account but also for this particular savings banks which are run through Postal Department should be given and restored back by the Government. Similarly, the commission is given to the agents. They are all poor people and are aged between 45 and 55 years; they cannot do any other job. They depend on small savings account holders. In many villages and towns, we can see that plenty of people are depending on money alone for their livelihood. Therefore, the State Government and also the Central Government should focus upon these aspects and see that these types of savings are utilised properly. Regarding the losses which are incurred by the Postal Department are very large. Thirty years ago, when the Budget was presented before the Parliament, the headlines would be, 'Postal card prices have increased. Postal cover prices have increased.' Nowadays, petroleum products and diesel prices are in the headlines. Now, the postal card alone is having a loss. The actual cost of making post cards is Rs. 697 crores but the earning is only Rs. 50 crores. Similarly, the registered single newspaper incurs Rs. 806 crores. Out of that, Rs. 99 crores is only the income. Rs. 1030 crores is the actual expenditure for registered newspaper bundles but the income is only Rs. 99 crores. Books posts, small packets are having an expenditure of Rs. 798 crores, but Rs. 661 is the only income. Printed books are also having an expenditure of Rs. 1338 crores, out of which only Rs. 355 crores is the income. Acknowledgment, I find only in South India. Normally, we used to get signatures on the acknowledgements, but, here, they will throw it out. Even though it is charged Rs. 597 crores, income is Rs. 300 crores. For registration, it is Rs. 3441 crores. Out of that, only Rs. 1700 crores

is the income. For Speed Post, it is Rs. 4437 crores; there is an income of Rs. 3493 crores. For Value Payable Post, it is Rs. 2063 crores; out of that, Rs. 423 crores alone are coming and for money orders, it is Rs. 6363 crores; out of that, Rs. 3517 crores are coming. The other one is Indian Postal Order. It is very surprising to note that the cost of postal orders is Rs. 2272 crores but income is only Rs. 323 crores. I am just suggesting, Sir, that we need not take away these projects, but it is high time that we look into these issues and find out why these losses are coming. Is it because of the undependability of the people who are managing it or is it because of the delay which is caused when you are competing with the other courier services? Therefore, we have to modernise it, make it available for the common man so that the people are attracted towards this particular service. Sir, the other one is the Department of Communications...(time-bell)...Sir, I was told that our party is left with 15 minutes. So, I am adjusting my views accordingly.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Another three minutes are left.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: I will finish it in ten minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Within?

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Ten minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Seven minutes?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Only three minutes.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Sir, next, I come to the Department of Communications.

SHRI RAHUL BAJAJ (Maharashtra): Sir, he is bargaining.

SHRI TARIQ ANWAR (Maharashtra): Sir, he is bargaining.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. No bargaining. The Whip has said not to allow more than the time allotted.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Sir, Village Public Telephone is very important. It is serving 5,58,549 villages as of April 30, 2009. But, it is strange to see that Village Public Telephones are going to serve as 'voice' instruments. It does not have any other service attached to it. Now, we are depending on telephones. When the Government has announced that Employment Exchanges would be connected and the people can register their name from anywhere through VPTs, there should be convergence. It should not only have the 'voice', but it should also have the telephonic messages and other computerised facilities so that the people in villages will be in a position to communicate through that. So, use the modern technology by which facilities could reach the other side. Sir, the strange thing is, from 2002 to 2009 — in 7 years — most of the tools used for this are going to be disbanded. New things are coming up.

New Multi Access Radio Relay is also going to come. Therefore, we have to find out why should we not go straightaway to broadband which, according to calculations, by 2010, we will have 40 million connections and there will be a demand for 20 million broadband connections. Wireless is, now, gradually occupying the place. The wire-line is now decreasing from 85.15 per cent to 8.83 per cent. Therefore, the huge investments that we are investing on wire-lines should be stopped and we have to go for the wireless services.

I conclude my speech with one aspect. When we — Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances and Pensions — go through the Annual Reports of various departments, we repeatedly tell all of them that they have to mention, as a corporate responsibility, in their Annual Reports, how many Scheduled Tribes are employed in their department, how many backlog posts of SC/ST/OBC and handicapped filled up. How many blind were given employment? When we had gone through all the Annual Reports, we found, except Postal Department, no department is mentioning about these details. Departments are not at all giving the figures. Even the backlog position is not given.

Finally, Sir, I would like to submit that the Extra-Departmental Employees' grievances have not yet been settled. Thousands of EDEs are getting meagre salary. This has to be settled immediately. The reason given in the Annual Report is that a case is pending before the High Court. The Court is not at all coming into the picture. The Department itself can settle it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have said that it is your final point, but, again, you are making another point.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: The Ministry has announced 'One India' Plan. Through this Plan, facility is given to customer to speak anywhere in the country with Re. 1. The announcement was made earlier. But, there is no follow-up to that. There was another Plan called '9.00 to 5.00.' Within the district telephone facility is allowed. But, now, this '9.00 to 5.00' has been taken away and the customer has to dial 'zero.' Why was it taken away? The pulse rate is very high. I would like to know from the hon. Minister how is he going to manage it.

I request the hon. Minister for release of a Postal Stamp on Rani Velunatchiyar, who was a great freedom fighter even before Rani Laxmibai, in her honour.

Sir, with regard to the Software Technology Parks of India, I would like to submit that these Parks are making very good effort. Even in Madurai, these Parks are doing well. But, the only problem is that they are limited to cities. Instead of that, if they go to the rural areas of Sivaganga, the people will be benefited. Thank you very much.

**श्री उपसभापति:** श्री राम नारायण साहू। आप चार मिनट में समाप्त कीजिए।

**श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश):** सर, 7 मिनट की बात हुई थी।

**श्री उपसभापति:** देखिए, आप argument मत कीजिए। आप के पहले स्पीकर ने 9 मिनट लिए हैं।

**श्री राम नारायण साहू:** सर, उसे रोकना आप का काम है।

**श्री उपसभापति:** अब मैं आप को रोकूंगा। आप की पार्टी के लिए जो टाइम allotted है, उसी में आप को भाषण पूरा करना चाहिए।

**श्री राम नारायण साहू:** जब अलग-अलग टाइम दिया है तो हम को पूरा टाइम मिलना चाहिए।

सर, हमारे पास बहुत से “डाटा” नहीं हैं और न मैं उनके ऊपर इतनी प्रैक्टिकल बातें कर सकता हूँ जिनका और लोगों ने हवाला दिया है, लेकिन मैं आम आदमी की बात करूंगा। सर, मृतक के आश्रितों को सर्विस देने की बात है। वैसे तो यह कमी सभी डिपार्टमेंट्स में है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में यह कुछ ज्यादा है। मृतक के आश्रितों के लिए जो 5 परसेंट का कोटा है, अगर उस कोटे से कुछ ज्यादा हो जाता है, अगर 6 परसेंट हो जाता है तो फिर आश्रितों को सर्विस नहीं मिलती है। सर, यह बड़ी दुखद बात है कि किसी का फादर सर्विस के दो-चार साल बाद मर जाए और यदि उसका यंग लड़का है तो उस को भी नौकरी नहीं मिल पाती है। सर, इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा। मंत्री जी मैं आप से भी निवेदन करूंगा कि आप इस बारे में जवाब जरूर दीजिएगा। सर, रेलवे विभाग भी भारत सरकार का ही है, लेकिन वहां यह कोटा नहीं है और यहां यह कोटा है। सर, यह बड़ी दुखद बात है। इसी तरह कस्टम डिपार्टमेंट में भी कोटा है। सर, एक बार मैं साउथ ब्लॉक चला गया। मैंने वहां एक बड़े अधिकारी से बात की कि इस लड़के को इतने दिनों से दौड़ाया जा रहा है। इसके फादर की डेथ हो गयी है, लेकिन इसे नौकरी नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि यह कानून तो आप लोगों ने बनाया है। उस बड़े अधिकारी ने एक किस्सा सुनाया। एक लड़का जिसकी उम्र 13 साल थी, उस के पिता की आतंकवादियों से लड़ते हुए मौत हो गयी और जब उस ने सर्विस के लिए apply किया तो उस से कहा गया कि अभी आप नाबालिग हो। अभी आप को नौकरी नहीं मिलेगी, जब बालिग हो जाओगे तब आप को नौकरी मिलेगी। वह लड़का जब 18 साल का बालिग हो गया और वहां गया तो उन्होंने उसे कहा कि इसके लिए तो आप को तीन साल के अंदर apply करना चाहिए था। सर, इसलिए इस कानून में बदलाव करना पड़ेगा। यह बदलाव होना चाहिए। सर, कई डिपार्टमेंट्स में, और मैं इसी डिपार्टमेंट की बात करना चाहूंगा कि वहां कर्मचारियों की कमी की वजह से काफी काम रुका पड़ा है, लेकिन वहां मृतक आश्रितों की भर्ती नहीं की जा रही है। इसलिए मंत्री जी इस बात को बड़ी गंभीरता से लें और मंत्री जी, प्लीज आप जवाब दीजिएगा।

सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि ये मोबाइल कंपनियां, टी.वी., अखबारों तथा अन्य contract देने वालों को रेवेन्यू की हिस्सेदारी का एग्रीमेंट करती हैं और बाद में कुछ क्लॉज में गड़बड़ी कर के बेईमानी का काम करती हैं। सर, इस में एक कंपनी है, जिस का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह बहुत आगे है। प्लीज इस घोटाले को रोका जाए।

**एक माननीय सदस्य:** नाम बताइए।

**श्री राम नारायण साहू:** मैं नाम नहीं बताऊंगा। यह पता लगाना आप का काम है।

सर, मैं मंत्री जी से — मंत्री जी जरा इधर ध्यान दें। मंत्री जी, मैंने एक बार इसी सदन में अनुरोध किया था और वह अनुरोध आपने मान भी लिया था। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे यह अनुरोध किया था कि हमारे जो कवि प्रदीप थे, उनके ऊपर और नौशाद अली के ऊपर डाक टिकट निकाली जाए। आपका लेटर भी हमारे पास आ गया है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप उनके ऊपर डाक टिकट निकालेंगे। मेरा आपसे एक विशेष अनुरोध यह है कि आप इन दोनों पर डाक टिकट निकालें। अगर यह आप उनके जन्म दिन पर निकालेंगे, तो बहुत अच्छी बात होगी। यह मैं आपसे विशेष अनुरोध करता हूँ।

बहुत से लोगों ने बी.एस.एन.एल. के टावर के बारे में बात बतायी। यह जगजाहिर है कि वास्तव में उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। इस पर मैं बहुत लम्बे में नहीं जाना चाहता, इसके लिए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा



कि इसके टावर बढ़ाये जाएं, क्योंकि connections बहुत ज्यादा हैं ...(समय की घंटी)... और इसकी रोकथाम के लिए इसके टावर बढ़ाये जाएं, तो इससे सुविधा होगी। देखिए, आपने चार मिनट पर घंटी बजा दी।

**श्री उपसभापति:** नहीं, नहीं। चार मिनट नहीं बल्कि छः मिनट के बाद मैंने bell बजाई है। मैंने आपको दो मिनट ज्यादा दिए हैं। आप बात कर रहे हैं, इसलिए आपको मालूम नहीं कि टाइम कितना निकल चुका है।

**श्री राम नारायण साहू:** सर, जो लैंड लाइन टेलीफोन है, उसके लिए जो security amount 1000 रुपये जमा कराया जाता है, वह बंद कराया जाए। जिसका जितना बिल आता है, उतनी ही पेमेंट ली जाए। वह जो एक permanent payment है कि इतना देना ही पड़ेगा, यह व्यवस्था हटायी जाए। ...(व्यवधान)... सर, सुना जाए।

**श्री उपसभापति:** हाँ बस। ...(समय की घंटी)...

**श्री राम नारायण साहू:** सर, बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी वजह से सन् 1980-85 में मोबाइल यहाँ आया। यह अच्छी बात है कि मोबाइल उनके कारण उस समय आया। यह बड़ी अच्छी बात है।

**श्री उपसभापति:** साहू जी, अब आप समाप्त कीजिए। आप जितना समय मांग रहे थे, उतना मैंने दे दिया है।

**श्री राम नारायण साहू:** सर, जब यहाँ पर मोबाइल आया, तो दूसरे देशों में उससे 25 साल पहले ही वह आ गया था। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि टेलीविजन यहाँ सन् 1955 में आया जबकि अमरीका में यह सन् 1932 में ही आ गया था। लोग तारीफ के ऊपर तारीफ करते हैं, लेकिन चर्चा ही नहीं करते हैं।

**श्री उपसभापति:** क्या करें?

**श्री राम नारायण साहू:** यह नहीं करना चाहिए, तभी हम बहुत पीछे हैं। ...(व्यवधान)... बिल्कुल ठीक बात है। ...(समय की घंटी)...

**श्री उपसभापति:** ठीक है। नेक्स्ट श्री साबिर अली।

**श्री राम नारायण साहू:** सर, ऐसा है कि अब मैं आपकी बात पर अनुशासन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं अनुशासनप्रिय हूँ। धन्यवाद।

**श्री साबिर अली (बिहार):** थैंक यू, सर। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, डी. राजा साहब नहीं हैं, यह शेर उन्हीं के लिए है:

*इधर-उधर की तू बात न कर, बता की काफ़िला क्यों लूटा,  
मुझे रहजनों की गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है,  
मैं बताऊँ काफ़िला क्यों लूटा, तेरे रहजनों से था वास्ता,  
मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।*

सर, मुझसे पहले इस सदन में इस मंत्रालय पर जितनी भी बातें थीं, उन्हें मेरे से सीनियर और दूसरी पार्टी के मैम्बर्स ने कही। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कहा और उन्होंने approximately 60,000 crores का आंकड़ा बताया। यह सदन जब भी चलता है, चाहे यह सदन हो या लोक सभा, हिन्दुस्तान के लोगों की नज़र इस सदन पर रहती है। सर, आई.टी. एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा क्षेत्र है, जिसके जरिये हिन्दुस्तान की पहचान दुनिया के उन मुमालिकों ने, उन कंट्रीज़ ने, उन देशों ने recognize किया, जो अपने आपको बड़े ताकतवर और बड़े तरक्कीयापता समझते थे। 1999 के बाद, हिन्दुस्तान के लोग जब हवाई जहाज में सफर करते हैं और बगल में बैठे गोरी चमड़ी के लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, अगर आप इंडिया कहिए तो आपको recognize करने लगेंगे। लेकिन, उससे पहले आपको हिकारत की नज़र से देखते थे। सर, मैं यह वास्ता दे रहा हूँ कि इस sector ने हमें सिर्फ revenue ही नहीं, इस sector ने हमें एक नई पहचान भी दी है। सर, यह sector जब से

आगे बढ़ा, इस देश में और देश के बाहर, इससे इस देश के लोगों को नौकरियां मुहैया हुई, कमोबेश 15 लाख लोग youngsters outsourcing पर Call Centres में काम करते हैं और इसी मंत्रालय में इससे पहले पांच साल जो मंत्री रहे ...**(व्यवधान)**... सर, हमारी बात को सुना जाए। यह बहुत बड़े मंत्री हैं, जिनके पास 6-6, 8-8 मंत्रालय हैं, इन्होंने आपको busy कर रखा है और जब मेरा समय होगा तो मुझे रोक दिया जाएगा। सर, इसी outsourcing के जरिए यहां करीब 15 लाख लोगों को नौकरी मिली। हमारे देश के लोगों ने trained होकर, IT Engineer बनकर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका आदि हर देश में जाकर अपनी पहचान बनाई। सर, यह ऐसा sector है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है। लेकिन, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सर, कि हम लोग इसमें करप्शन की बात करते हैं, इस पर उंगली उठाते हैं। हमारे यहां इसी सदन में कम से कम 10 Questions हुए हैं एक कम्पनी पर। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** साबिर अली जी, एक मिनट रुकिए, मंत्री जी कुछ बोलेंगे। आप बैठ जाइए।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, the Lok Sabha will be taking up the Demands for Grants Guillotine at 6 o'clock. All Ministers will have to be present in Lok Sabha, in case some Cut Motions are pressed. So, I will have to request you, Sir, to kindly consider adjourning the House before that. If we can finish it before that, it will be good.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is why I said that there are only three speakers from the Congress, I would like them to withdraw their names if the Whip is there. ...**(Interruptions)**... That is what I am saying. ...**(Interruptions)**... It can be adjourned at 5.45 p.m. Then, there are three speakers from 'Others'. I request them to please take three-four minutes and finish. In any case, we have to end the debate.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Sir, the Minister can reply tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In any case, the reply will be not tomorrow, but on some other day. But, by 5.45 p.m., it has to be adjourned.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, list it for tomorrow. If possible, it can be tomorrow. Otherwise, it can be on some other day.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is always the case. But tomorrow, since there is Calling Attention, it will be difficult.

SHRI S.S. AHLUWALIA: But list it for tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will do it. साबिर अली जी, आप एक मिनट में खत्म कीजिए।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: But discussion can also continue tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no; discussion is not possible.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: If you want to complete today ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; Mr. Bagrodia, we have to complete it.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I want only two minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Yes, Mr. Sabir Ali.

**श्री साबिर अली:** सर, मैं जिस कम्पनी का नाम लेना चाहता हूँ उसका नाम already on the record है — SWAN कम्पनी, जिस पर कांग्रेस के लोगों और दूसरे लोगों ने, हमने भी questions किए, इस सदन में उनका जवाब भी दिया गया। इससे पहले भी उसकी चर्चा दूसरे लोगों ने की है, मैं उसको repeat नहीं करना चाहता हूँ। SWAN एक ऐसी कम्पनी है जो मुम्बई based ऐसे लोगों की कम्पनी थी, जिनका टेलिकम्युनिकेशन से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं था और उसमें joint venture करके दुबई में डेल्टा के नाम से एक कम्पनी बनाई गई और यह ऐसी कम्पनी बनाई गई जो बिल्कुल dummy थी और उसको share allot किया गया। ...**(समय की घंटी)**... सर, दो मिनट लूंगा, मेरा समय बाकी है।

**श्री उपसभापति:** टाइम नहीं है, पांच मिनट आपको दे दिए गए हैं।

SHRI SABIR ALI: Sir, just two minutes. I would not exceed.

**श्री उपसभापति:** अब detail में जाने का समय नहीं है।

**श्री साबिर अली:** Okay; Sir. I will not exceed. I will conclude.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If there is anything, you can write a letter to the Minister and he will reply.

**श्री साबिर अली:** सर, उस कम्पनी ने, जैसा कि कहा गया कि कम्पनी को जब licence allot कर दिया गया, within two days, उस कम्पनी ने 10 lakh शेयर जो दुबई based कम्पनी है, उसके साथ joint venture किया और उस joint venture में 4,500 करोड़ रुपए लिए गए। सर, अपनी बात को conclude करने से पहले मैं इस सदन को कहना चाहता हूँ कि हम लोग बात करते हैं corruption की और इतनी बड़ी corruption, जो इसमें सामने आ रही है 60,000 करोड़ की, यह तो सिर्फ थोड़े दिनों का calculations है। 1999 से लेकर आज तक अगर इस डिपार्टमेंट में हुई गड़बड़ियों का आकलन किया जाए, तो कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और जिन लोगों ने यह घोटाला किया है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर उन लोगों का नारको टेस्ट कराया जाए, तो इस देश को 20 लाख करोड़ रुपए within a certain period वापस मिल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Mr. Deputy Chairman Sir, I wanted to speak for a longer period, but in view of the circumstances, I would like to raise only one point, which the Leader of the Opposition has mentioned. He has mentioned about 2G spectrum not being allotted or auctioned. I wish to say that at that time, to the best of my memory, nobody was willing to take these licences because nobody knew what is going to happen. Actually, those who have taken them have taken a big risk; they have paid thousands of crores of rupees to get the licences. That is one aspect. Business concept is entirely a different thing, which the hon. Leader of Opposition could probably not understand. ...**(Interruptions)**... I would like to know whether the NDA, during its regime, had auctioned a single asset of the country. They sold a hotel in Bombay for Rs. 100 crores, which was re-sold for about Rs. 400 crores in three months'

time! What are they talking about? So, let us understand that these things that were done, were done in the best interest of the country at that time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Bharkatumar Raut. Just two minutes.

SHRI BHARATKUMAR RAUT (Maharashtra): Sir, I would be talking only about the working of MTNL, Mahanagar Telephone Nigam Limited, that works in Mumbai and in Delhi. I am talking about it because it is the lifeline of these two metros. Also, it is very important for the IT and Communications Ministry because ever since the MTNL was formed 23 years ago, it has contributed Rs. 33,000 crores to the national exchequer by way of income tax, dividends and others. However, I wish to draw the attention of the Minister to the fact that the employees of MTNL have been deprived of their legitimate right of Government pension that has been given to the employees of DoT, the Ministry of Communications, and now, the BSNL. There was an agreement with BSNL as per which a 30 per cent wage hike was given and benefits of the Sixth Pay Commission were given, but MTNL employees have been deprived of any such benefit. More than that, Sir, there was a wage revision agreement between MTNL employees and the Ministry in 2007. We are already half way through 2009 and that agreement has still not been implemented. Sir, when MTNL was formed, the employees who were earlier working with the Ministry of Communications or DoT were transferred without their consent. They were sent to MTNL with an assurance in 2002 that the same service rules that governed them when they were in the Ministry would be applicable to them when they are employed in MTNL. The then Communications Minister, late Shri Pramod Mahajan, had given them the assurance that it would be done. Now seven years have passed and nothing has happened. Last year, Mr. Minister will remember, I had raised this issue on the floor of this House. Even at that time an assurance was given. I have got with me the written assurance that the Government would take the decision as soon as possible. That 'as-soon-as-possible' is yet to happen. ...(Time-belling)... Sir, you have not given me time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have given you three minutes. Your time is over.

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): MTNL employees का ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपके बोलने से disturbance होगी, वे जो बोलेंगे, मंत्री जी नहीं सुन पाएंगे ...(व्यवधान)...

SHRI BHARATKUMAR RAUT: Sir, I wish to bring a more important point to your notice, the policy of employment. I shall cite only one example because of the paucity of time. Very recently, an advertisement of some jobs in Mumbai was brought out; that advertisement appeared only on the website. Sir, I would like to know if, in this country, all the eligible candidates have access to the Internet; they don't. Even then, the advertisement appeared only on the website. After a demand was made by us, it appeared in some newspapers, but in a five-centimeter column. After that, 14,000 candidates applied for 319 posts. All the posts are in Mumbai. Out of 319

vacancies, only 14 Marathi-speaking candidates were selected. Why did it happen? I am not talking about provincialism. But if the posts are in Mumbai, the sons of soil should be given the preference...*(Interruptions)*...

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): You cannot have people on the basis of language. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Seelam, leave it. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHARATKUMAR RAUT: I am just saying that if posts are in Gujarat, Gujaratis should be given the preference and if they are in Bengal, then Bengalis should be given the preference. ...*(Interruptions)*...

SHRI JESUDASU SEELAM: No Gujarati, no Marathi. It is an all-India service. ...*(Interruptions)*... It is an all-India service. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Whatever he is saying is not going on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI JESUDASU SEELAM: \*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not permitted you. ...*(Interruptions)*... It will not go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI JESUDASU SEELAM: \*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record except Mr. Raut's speech. ...*(Interruptions)*... आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*... आप बैठिए। राऊत जी आप बोलिए। ...*(व्यवधान)*... पाणि जी, आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*...

**श्री रुद्रनारायण पाणि: \***

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Pany, nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHARATKUMAR RAUT: I demand that this recruitment process has to be stopped and reviewed. I also demand to re-advertise it again. Give preference to sons of soil. There should be a policy by MTNL to see that the local people are given employment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sharad Anantrao Joshi. You have three minutes.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Sir, shall I lay the papers?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, that system is not there.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: I refuse to speak. I don't want to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is urgency. After that, no Minister will be there. They have to go to Lok Sabha.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: They can go to Lok Sabha. I have no objection. ...*(Interruptions)*... I forego my chance.

---

\*Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Shri Rajniti Prasad.

**श्री राजनीति प्रसाद (बिहार):** सर, मेरे पास कितना समय है।

**श्री उपसभापति:** आप एक-दो मिनट ले लीजिए।

**श्री गिरीश कुमार सांगी (आन्ध्र प्रदेश):** सर, आप जोशी जी को पांच मिनट दे दीजिए।

**श्री उपसभापति:** मैं देना चाह रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... But I have to ration the time. ...**(Interruptions)**... He has refused to speak. What can I do? ...**(Interruptions)**... I told Mr. Raut to speak in three minutes, but I gave him five minutes. I could have given him five minutes also. ...**(Interruptions)**...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: You normally give extra time. On the Railway Budget, I saved one minute out of those five minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is correct.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: I have never exceeded the time limit.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You speak now and complete it.

**श्री कमाल अख्तर (उत्तर प्रदेश):** सर, बात यह है कि चेहरा देखकर समय दिया जाता है।...**(व्यवधान)**... या तो इधर देखा जाता है या उधर देखा जाता है।...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** यह सही नहीं है। आप कुछ मत कहिए। पूरा टाइम रिकॉर्ड होता है। इस तरह से सदन का टाइम वेस्ट होता है। जोशी जी, आप बोलिए।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Before getting into public life, Sir, I was in the Telecommunications Department of the Government of India, and I was also in the International Telecommunications Union in Geneva. I have some special points to make on this subject. To accommodate your constraints, Sir, I would limit myself only to Telecommunications and not to talk about the Information-Technology. Sir, while talking about the General Budget, I had made the point that the so-called inclusive growth has its own limitations. If you see the history of different nations, factors that have resulted in rapid growth are technological innovations, wars, Diaspora and free trade and competition. I would like to say that the grand success story that the telecommunications represents in India is a good example of this particular model. Sir, When I started farmers' agitation and whenever there was an agitation or a rally, at the end the media persons used to rush to the nearest post office and try to book what used to be called, at that time, the lightning calls and those lightning calls generally took about two to three hours to materialise. If we applied for a telephone connection, it took, at least, two to three years and that too if you had some kind of political connection. Today, the situation has greatly changed, and, I think, it has changed largely because of the fact that the new technology that came and the Government was liberal enough to allow the new technology with the result that we have two contrasts. Sir, two services come in our houses by cables. One is the telephone and the second is the power, that is, electricity. We find that where we permitted liberal technology, today, even the ordinary farm worker can flash out his little cell and talk on telephone to anybody whom he

likes. On the other hand, we are seriously constrained about the power supply. Sir, it would be a good idea if the Government of India follows the model of the Telecommunications Department, permits full licence to the individual enterprise, individual initiative and competition and then, they would not have to talk the politically attractive slogans of inclusiveness and *aam admi*. The Telecommunication Department should provide the right path and right prescription to growth.

**श्री राजनीति प्रसाद :** सर, मैं दो बात कहना चाहूंगा। पहले तो यह कि जो डाक की व्यवस्था है, पोस्ट आफिस की व्यवस्था है, वह गांवों में समाप्त हो गई है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गांवों में जो पोस्ट आफिस की व्यवस्था है उसको पुनः चालू करने की कृपा करें। सर, दूसरी बात, गांवों के पोस्ट आफिसेज में बहुत लोग लगे हुए हैं तथा पूरे हिन्दुस्तान में कई हजार लोग हैं। इस काम में लगे हुए इन लोगों की, किसी की उम्र 50 साल हो गई है, किसी की 40 साल हो गई है, जो अब दूसरी नौकरी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे डाक विभाग से लगे हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए उनको रेग्यूलराइज करना चाहिए तथा इनके लिए जल्दी से कोई कार्यक्रम बनाना चाहिए। सर, एक अंतिम बात, क्योंकि आपको भी जल्दी है और हम आपको कोआपरेट करना चाहते हैं।

एम.टी.एन.एल. की जो हेल्प लाइन है, कृपया करके उस हेल्प लाइन को ठीक करने का काम करिए, क्योंकि मुझको जो सूचना मिली है कि सात बजे से लेकर साढ़े नौ बजे तक और 7-30 बजे के बाद वह कभी भी लगती नहीं है। उसमें कम्प्यूटर बोलता रहता है, “You are in queue.”, But, I do not know how long people will stand in queue. इसलिए यह तीन बात बोल करके मैं समाप्त कर रहा हूं और मैं आपको कोआपरेट कर रहा हूं। आपका धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the discussion on the working of the Ministry of Communications and Information Technology is concluded. The reply will be tomorrow.

#### SPECIAL MENTIONS

##### **Demand to Commemorate the Victory of Kargil every year**

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (Karnataka): Sir, I draw the attention of the hon. Members to the tenth anniversary of the victory of the men and women of our Armed Forces over our enemies at Kargil on the 26th July.

This day represents not just the victory of our proud country and its will prevailing over those of its enemies, but also most importantly, it represents the inspirational sense of duty and sacrifice by thousands of men and women of our Armed Forces.

I remember every day of that conflict as do many Indians. These are the men and women whose actions, sense of nationalism and duty which should inspire our younger generations. I believe the actions of the men and women of our Armed Forces in that conflict and every other conflict deserve our *shradhanjali*, respects and salutes. I appeal to the Ministry of Defence and the Government to memorialise this day and celebrate it every year. I also appeal to my colleagues in this House to join me in this demand. It is our duty to our nation to memorialise these acts of sacrifice and duty.